

सबका जम्मू कश्मीर

हिन्दी • वर्ष: 2 • अंक: 1 • कठुआ, शनिवार 3 जनवरी 2026 • पृष्ठ: 16 • मूल्य: 5 रूपए

कटरा, शिव खोरी में हेलीपैड का निर्माण अंतिम चरण में : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। अपने दीक्षांत भाषण में, सिन्हा ने बदलते विश्व की मांगों को पूरा करने के लिए पुरानी, छहटने वाली शिक्षण प्रणाली से अधिक आधुनिक और कौशल-आधारित शिक्षण पद्धतियों की ओर बढ़ने की अनिवार्यता के बारे में बात की।

शनिवार को एसएमवीडीयू के 11वें दीक्षांत समारोह के दौरान एलजी मनोज सिन्हा छात्रों और अन्य लोगों के साथ मौजूद थे। शनिवार को एसएमवीडीयू के 11वें दीक्षांत समारोह के दौरान एलजी मनोज सिन्हा छात्रों और अन्य लोगों के साथ मौजूद थे।

"हमारा प्रयास पाठ्यक्रम के बोझ को



कम करना और भविष्य की नौकरियों के लिए अनुकूलनीय कौशल विकसित करना होना चाहिए।

यदि किसी उच्च शिक्षा संस्थान का एक भी छात्र बेरोजगार है या अपना उद्यम

स्थापित नहीं कर पा रहा है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि शिक्षण संस्थान और उसके शिक्षकों ने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया है," उन्होंने कहा।

उपराज्यपाल ने छात्रों से जीवन में नए

रास्ते बनाने, जीवन को नई दिशा देने, नए पहलुओं का पता लगाने और राष्ट्र की समृद्धि के लिए नए तरीके सुझाने का आह्वान किया। "2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक छात्र, प्रत्येक शिक्षण संस्थान को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी क्योंकि भविष्य और उसका विकास ज्ञान अर्थव्यवस्था पर आधारित होगा," उन्होंने कहा। उपराज्यपाल ने तकनीकी परिवर्तन और 21वीं सदी के कार्यबल की मांगों के साथ तालमेल बिठाने के लिए पांच समाधान दिए।

"शिक्षण, अधिगम और विश्वविद्यालय संचालन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करें और प्राथमिकता के आधार पर नए तकनीकी उपकरणों को अपनाएं। रटने की पद्धति से हटकर आजीवन, लचीले

■ होष पेज 2...

सभी 20 डीडीसी को लगभग दो महीने के लिए नई ऊर्जा मिलती है

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू और कश्मीर में बीस जिला विकास परिषदों (डीडीसी) - प्रत्येक 20 जिलों में एक - को सरकार के विधि विभाग की राय के बाद लगभग दो महीने का नया जीवनदान मिला है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि उनका कार्यकाल 27 दिसंबर, 2025 के बजाय 24 फरवरी, 2026 को समाप्त होगा।

जम्मू और कश्मीर में पहली बार गठित पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों को पूरा करने वाली डीडीसी (विभागीय विकास परिषद) के पांच वर्षीय कार्यकाल की गणना को लेकर पहले एक पेचीदा स्थिति उत्पन्न हो गई थी। डीडीसी सदस्यों ने 28 दिसंबर, 2020 को शपथ ली थी,

■ होष पेज 2...

45 प्रतिकूल घटनाएं बर्ही; 77 प्रतिकूल घटनाएं और प्रतिकूल घटनाएं स्थानांतरित हुईं, जिन्हें पीडीडी में पीडी दर्ज किया गया



सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : सरकार ने आज विद्युत विभाग के 39 प्रभारी सहायक अभियंताओं (एई) को प्रभारी सहायक कार्यकारी अभियंताओं (एईई) के पद पर पदोन्नत/स्थापित किया और

विद्युत विकास विभाग (पीडीडी) में 77 प्रभारी एईई और प्रभारी एईई का तबादला/तैनात किया।

आई/सी एईई (25 डिग्री धारक) के रूप में पदोन्नत किए गए लोग हैं: विशाल शर्मा, विना. 'द माथुर, सईद अहमद फारूकी, मोहम्मद अशरफ, रिप्पन कुमार,

मसूद-उल-शरीफ जरगर, तालिब हुसैन गिलानी, सुनील कुमार, खुर्शीद अहमद भट्ट, विजय कुमार, प्रेरणा भगत, अमजद परवेज, नवनीत गुप्ता, परशोतम कुमार, केशव चंदर खजूरीया, मोहम्मद खान, पृथ्वीपाल सिंह, मुश्ताक अहमद, हकीम-उद-दीन खान, राकेश कुमार बंगोत्रा, मकबूल हुसैन, पवन कुमार, साजदा बेगम, मोहम्मद रफीक खान और विजय कुमार शर्मा।

डिप्लोमा धारक 15 लोगों को प्रभारी सहायक कर्मचारी (एईई) के पद पर पदोन्नत किया गया है: शाह मेहरोज अहमद, गौहर रफीकी, अनुराधा गुप्ता,

■ होष पेज 2...

कश्मीरी पंडितों की सांस्कृतिक, भाषाई, सभ्यतागत लोकाचार का संरक्षण आवश्यक : डॉ. जितेंद्र

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : कश्मीरी पंडित समुदाय की सांस्कृतिक और भाषाई परंपराओं के लगातार कमजोर होते स्वरूप पर चिंता व्यक्त करते हुए, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कश्मीरी पंडित विरासत को संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि कश्मीर की मिश्रित संस्कृति को बनाए रखने के लिए समुदाय की सांस्कृतिक, भाषाई और सभ्यतागत परंपराओं का संरक्षण आवश्यक है, जो कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरी है।

मंत्री जी ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले ग्यारह वर्षों में जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक और निरंतर



कार्रवाई की है, जिसके परिणामस्वरूप आतंकी घटनाओं, पत्थरबाजी और लक्षित हत्याओं में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि यह मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है और आतंकवाद से निपटने में दृढ़ता की कमी वाले पूर्व के दृष्टिकोण से एक स्पष्ट बदलाव है।

डॉ. जितेंद्र सिंह यहां पंडित प्रेमनाथ भट्ट के शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। पंडित प्रेमनाथ भट्ट एक प्रख्यात वकील, पत्रकार और आरएसएस विचारक थे, जिनकी 27 दिसंबर, 1989 को आतंकवादियों ने हत्या कर

■ होष पेज 2...

उच्च न्यायालय : गंभीर अपराधों के मामलों में निचली अदालतों को साक्ष्य बंद करने से बचना चाहिए

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों से हत्या जैसे जघन्य अपराधों में साक्ष्य को छिपाने से परहेज करने पर जोर दिया है, क्योंकि इससे न्याय में विफलता हो सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने से बचकर मुकदमे को लंबा खींचने के लिए इसका दुरुपयोग न करे।

न्यायमूर्ति संजय धर ने कहा कि यद्यपि निचली अदालत के पास अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को बंद



करके मुकदमे को समाप्त करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हत्या जैसे

जघन्य अपराधों में, अदालतें आमतौर पर यह चरम कदम नहीं उठाती हैं, विशेषकर तब जब जांच के लिए पेश किए जाने वाले गवाह विशेषज्ञ गवाह और जांच अधिकारी हों।

न्यायमूर्ति धर ने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में साक्ष्यों को बंद करने से परहेज करती हैं, अन्यथा इससे न्याय में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

ये टिप्पणियां अदालत ने फहद मकसूद खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं, जिस पर हत्या का आरोप है और जो पिछले 13 वर्षों से जेल में है क्योंकि मामले की सुनवाई साक्ष्य

चरण में है। खान ने केवल अपनी लंबी कैद और शीघ्र सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर जमानत मांगी है।

"...अदालत ने पाया है कि याचिकाकर्ता ने 13 वर्षों से अधिक समय तक कारावास में रहने और अभियोजन पक्ष और पुलिस विभाग के आचरण के कारण निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की संभावना न के बराबर होने के कारण जमानत देने का आधार बनाया है," अदालत ने कहा। "उसने धारा 483 के तहत जमानत पर रिहाई की मांग

■ होष पेज 2...

कटरा, शिव खोरी...

और कौशल—केंद्रित अधिगम मॉडल को अपनाएं। उद्योग और अन्य संस्थानों के साथ मजबूत साझेदारी विकसित करें। अनुभवात्मक अधिगम पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए।” लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, “विशेष रूप से मानविकी के छात्रों को यह समझने की आवश्यकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित दुनिया में, मशीनों द्वारा प्रदान न की जा सकने वाली चीजों का महत्व बढ़ेगा। नवाचार, अनुसंधान और सामाजिक सेवा, अत्याधुनिक अनुसंधान और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।”

उन्होंने विज्ञान, मानविकी और प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति के मानव सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए शिक्षण समुदाय की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कक्षा शिक्षण पद्धतियों को इन बदलावों के अनुरूप विक. सित होना चाहिए, ताकि आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति दोनों को गति मिल सके।

उन्होंने कहा, “कक्षा और हमारी शिक्षा को छात्रों को बेहतर जीवन बनाने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और अधिक प्रबुद्ध समाज का निर्माण करने के लिए तैयार करना चाहिए।”

सिन्हा ने भारत के शैक्षिक परिदृश्य में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के विशिष्ट योगदान और जन कल्याण के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की।

उन्होंने महिला छात्रों को उनकी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धियों और उत्कृष्टता के नए मानदंड स्थापित करने के लिए बधाई भी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सामने आने वाली चुनौतियों के वैज्ञानिक समाधान प्रदान करने का दायित्व श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय को सौंपा।

हाल ही में आई विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं के महेनजर, सिन्हा ने विश्वविद्यालय से बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ के लिए उन्नत पूर्व चेतावनी प्रणालियों पर अनुसंधान को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने सतत अवसंरचना के महत्व पर भी बल दिया और सड़क और निर्माण सामग्री के पुनर्चक्रण और पुनरु उपयोग पर समर्पित अनुसंधान का आह्वान किया।

उपराज्यपाल ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय को डोगरी और वैदिक अध्ययन के पाठ्यक्रमों को पुनर्रचना करने का निर्देश दिया ताकि इन विषयों को अधिक आकर्षक और समकालीन बनाकर अधिक छात्रों को आकर्षित किया जा सके। उन्होंने जीर्ण-शीर्ण अवस्था में चल रहे इंडोर स्टेडियम के शीघ्र निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने का भी निर्देश दिया।

उपराज्यपाल ने हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों की राहत और पुनर्वास में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने संस्कृत और वैदिक शिक्षा के लिए समर्पित संस्थानों को सहयोग देकर सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति बोर्ड की निरंतर प्रतिबद्धता की प्रशंसा की।

उन्होंने बताया कि श्राइन बोर्ड ने रियासी और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से 22 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुएं खरीदी हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने श्राइन बोर्ड के सीईओ को स्थानीय निवासियों से अधिकतम खरीद करने का निर्देश दिया है ताकि उनकी आजीविका को समर्थन मिल सके।

उपराज्यपाल ने आगे बताया कि श्राइन बोर्ड ने जिले में शंकराचार्य मंदिर के साथ-साथ पांच अन्य मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू किया है, जबकि कटरा में देवी का एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया जाना है।

“कटरा और शिव खोरी में हेलीपैड का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। मुझे उम्मीद है कि आगामी महाशिवरात्रि के दौरान श्रद्धालु कटरा से शिव खोरी मंदिर तक हेली-सेवा का लाभ उठा सकेंगे”, उन्होंने कहा।

इस अवसर पर उपराज्यपाल ने श्हाई-एंड कंप्यूटिंग एआई और डीप लर्निंग लैब्स और श्विवाहित छात्रों के लिए आवासश का उद्घाटन किया।

दीक्षांत समारोह में 228 मास्टर्स, 26 डॉक्टरेट और 567 स्नातक डिग्री सहित 821 डिग्रियां प्रदान की गईं। मेधावी छात्रों में से 25 (7 लड़के और 18 लड़कियां) को पदक भी दिए गए। कुल 10 छात्रों (4 लड़के और 6 लड़कियां) को इंफोसिस फाउंडेशन का उत्कृष्टता पुरस्कार मिला, जबकि 11 छात्रों को विशिष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर जिला विकास परिषद रियासी के अध्यक्ष सरफ सिंह नाग; श्री माता वैष्णो देवी के विधायक श्री बलदेव राज शर्मा; संभागीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार; सूचना एवं आपातकालीन सरक. ारी अधिकारी जम्मू भीम सेन तुती भी उपस्थित थे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ सचिन कुमार वैश्य; रियासी की उपायुक्त निधि मलिक और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. (डॉ.) प्रगति कुमार ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के पूर्व अध्यक्ष प्रो. टी.जी. सीताराम; श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदस्य डॉ. अशोक भान और श्रीमती गुंजन राणा; उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त

मुख्य सचिव श्री शांतमनु, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य और छात्र इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित थे।

सभी 20 डीडीसी....

जबकि परिषदों का औपचारिक गठन 25 फरवरी, 2021 को हुआ था। यह भ्रम कार्यकाल की तारीख को ध्यान में रखने को लेकर था, जिसमें सदस्यों द्वारा शपथ लेने की तारीख या निकायों के गठन की तारीख को शामिल किया गया था।

आधिकारिक सूत्रों ने एक्सेलिसयर को बताया कि सरकार के विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग, जिसे ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा यह मुद्दा भेजा गया था, ने कहा है कि डीडीसी को उनके गठन की अधिसूचना जारी होने की तारीख, यानी 25 फरवरी, 2021 से विधिवत गठित माना जाएगा।

विधि विभाग ने अपने मत के समर्थन में जम्मू और कश्मीर पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 108c के उप-नियम (2) और उप-नियम (3) का हवाला दिया है। उप-नियम (2) में यह प्रावधान है कि निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के नाम प्राप्त होने पर सरकार अधिसूचना द्वारा संबंधित जिले के नाम से जिला विकास परिषदों का गठन करेगी। सूत्रों के अनुसार, उप-नियम (3) में कहा गया है कि उप-नियम (2) के तहत ऐसी अधिसूचना जारी होने पर जिला विकास परिषद विधिवत गठित मानी जाएगी।

कानूनी राय के अनुसार, जिला विकास परिषदों का पांच वर्षीय कार्यकाल अब अगले वर्ष 24 फरवरी को समाप्त होगा।

सूत्रों ने बताया, यदि शपथ ग्रहण दिवस, यानी 28 दिसंबर, 2020 को जिला विकास परिषदों के पांच वर्षीय कार्यकाल की गणना में शामिल किया जाता, तो परिषदें आज अस्तित्व में नहीं होतीं। उन्होंने आगे कहा कि अब उन्हें लगभग दो महीने का नया जीवन मिला है।

जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 के अनुसार, जिला विकास परिषद का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, सिवाय उन मामलों के जहां पंचायतों के सभी स्तरों के लिए एक साथ आम चुनाव कराए जाते हैं ताकि जिले में सभी स्तरों का कार्यकाल समान हो।

प्रत्येक जिला विकास परिषद में 14 निर्वाचित सदस्य होते हैं। जम्मू और कश्मीर में 20 जिले हैं, इसलिए निर्वाचित जिला विकास परिषद सदस्यों की कुल संख्या 280 है।

हालांकि, केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा जिला विकास परिषदों के चुनाव कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाने के कारण, पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर 24 फरवरी, 2026 से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पंचायतों, नगरपालिकाओं और ब्लॉक विकास परिषदों (बीडीसी) का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है।

जम्मू क्षेत्र में भाजपा छह परिषदों में सत्ता में है, जबकि नेशनल कॉन्ग्रेस तीन निकायों पर शासन कर रही है। पुंछ डीडीसी की अध्यक्ष एक निर्दलीय हैं। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी और डोडा जिलों में भाजपा सत्ता में है, जबकि राजौरी, किश्तवार और रामबन में डीडीसी का नेतृत्व नेशनल कॉन्ग्रेस कर रही है। पुंछ डीडीसी की अध्यक्ष एक निर्दलीय महिला पार्षद हैं।

पंचायतें, नगरपालिकाएं और ब्लॉक विकास परिषदें लगभग दो साल पहले समाप्त हो गईं, जबकि डीडीसी का कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर में धूमधाम से स्थापित पंचायती राज की तीनों संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी।

राज्य विधानसभा क्षेत्रों (डीडीसी), नगरपालिकाओं, पंचायतों और बीडीसी के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) पिछले आठ महीनों से निष्क्रिय है और कोई आयुक्त नियुक्त नहीं है। इस वर्ष अक्टूबर में श्रीनगर में हुए पिछले विधानसभा सत्र में सरकार ने एसईसी की अधिकतम आयु सीमा से संबंधित एक विधेयक पारित किया था।

45 प्रतिकूल घटनाएं...

निशी बाला, रेखा ज़ारू, स्वाइबा जान कादरी, रवि जी कौल, अरविंद शर्मा, रजनी शर्मा, वसीम सज्जाद, रूबी जान, शमाश कालू, रीता गुप्ता, रंजय गुप्ता और मोहम्मद इकबाल वदू।

उपरोक्त नियुक्तियों के परिणामस्वरूप, आज 77 प्रभारी सहायक कर्मचारी (एईई)/एईई का तबादला/पोस्टिंग की गई। सैयद फारुक को डिवीजन-८ जेकेपीसीएल में; मोहम्मद अशरफ को एसडी तंगधार ईडी कुपवाड़ा केपीडीसीएल में; विशाल शर्मा को एसडी रामकोट ईडी कठुआ जेपीडीसीएल में; रिपेन कुमार को एसडी-८ एसएलडीसी, जेकेपीटीसीएल जम्मू में; मसूद उल-शरीफ को एसडी-८ ईडी डोडा, जेपीडीसीएल में; विनोद माथुर को एसडी-८ ईडी डोडा जेपीडीसीएल में; तालिब हुसैन को ईडी शोपियां, एसडी शोपियां केपीडीसीएल में तैनात किया गया है। सुनील कुमार को एसडी-रामगढ़ ईडी विजयपुर जेपीडीसीएल; खुर्शीद अहमद से एसडी-लंगेट, ईडी हंदवाड़ा; विजय कुमार को एसडी धर्मासी ईडी रियासी; प्रेरणा भगत को निरीक्षण मंडल जम्मू; अमजद परवेज़ को एमडी, जेकेपीडीसी कार्यालय; नवनीत गुप्ता को जहांगीर अहमद के स्थान पर एक्सईएन एसटीडी-८ जेपीडीसीएल में तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया; पुरुषोत्तम कुमार को ईडी-८, एसडी प्लांट जेपीडीसीएल भेजा गया; केशव चंदर को

ईडी-८, एसडी नहर जेपीडीसीएल; मोहम्मद खान को तकनीकी अधिकारी के रूप में ईडी पुंछ में नियुक्त किया गया; पृथपाल सिंह को योजना मंडल जेपीडीसीएल, जम्मू; मुश्ताक अहमद को एसडी-द्वितीय ईडी बारामूला केपीडीसीएल; हकीम-उद-दीन से एसडी नवाकदल ईडी-८ केपीडीसीएल; राकेश कुमार को कॉर्पोरेट कार्यालय, एमडी जेकेपीटीसीएल; मकबूल हुसैन से एसडी मेंढर ईडी पुंछ; पवन कुमार एसडी बिलावर ईडी कठुआ; मोहम्मद रफीक को ईडी-द्वितीय, एसडी हज़ूरीबाग; साजदा बेगम से ईडी-८, एसडी नगरोटा; विजय कुमार शर्मा से एसडी कोटरका, ईडी राजौरी; शाह महरोज़ से ईडी-८, एसडी पथरमसिजद; एमडी जेकेपीडीसी के निपटान में गौहर रफीकी; अनुराधा गुप्ता को टीएलएमडी-८ उधमपुर, एसडी-८ जेकेपीटीसीएल; निशि बल्ला से एसडी स्टोर, टीएलएमडी-८ जेकेपीटीसीएल; रेखा ज़ारू को डिवीजन-८ जेकेपीसीएल; स्वाइबा जान से साइबर सुरक्षा एलडीसी जेकेपीटीसीएल कश्मीर; रवि जी कौल को टीएलएमडी-८ जम्मू से एक्सईएन को टीओ बनाया गया; अरविंद शर्मा को ईडी-८ परेड जेपीडीसीएल में एक्सईएन के रूप में टीओ; रजनी शर्मा को प्लानिंग एसई प्लानिंग सर्कल जेपीडीसीएल जम्मू की ओ/ओ नियुक्त किया गया; वसीम सज्जाद को एसटीएफ बिजबेहरा केपीडीसीएल में टीओ के रूप में एक्सईएन; रूबी जान से टीएलएमडी-८ एसडी-८ अमरगढ़ जेकेपीटीसीएल; शमास कालू को प्लानिंग सर्कल जेपीडीसीएल; रीता गुप्ता को ओएंडएम सर्कल जम्मू से टीओ से एसई; मोहम्मद इकबाल वाडू को एसडी बनिहाल से ईडी बटोटे जेपीडीसीएल और रंजय गुप्ता को एसडी-८ सिधरा टीएलएमडी-वी जेकेपीटीसीएल, जम्मू।

कश्मीरी पंडितों की...

दी थी। पंडित प्रेमनाथ भट्ट को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंत्री जी ने कहा कि उनका बलिदान आतंकवाद और लक्षित हिंसा के कारण कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा झेली गई पीड़ा का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि आतंकवाद ने गंभीर मानवीय पीड़ा पहुंचाई और कश्मीर की सामाजिक सद्भाव को बुरी तरह से बाधित किया। उन्होंने कहा कि कई वर्षों तक आतंकवाद की चयनात्मक और असंगत परिभाषा के कारण आतंकवाद के पीड़ितों, विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों के मानवाधिकारों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि इससे उन लोगों के साथ होने वाला अन्याय और बढ़ गया जिन्हें अपने घर छोड़ने और अपनी पैतृक जड़ों से नाता तोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय ने दशकों के विस्थापन और कठिनाइयों के बावजूद असाधारण लचीलापन और जीवित रहने और फलने-फूलने की अंतर्निहित क्षमता का प्रदर्शन किया है।

कश्मीर की सदियों पुरानी मिश्रित और बहुलवादी संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कश्मीरी पंडित घाटी की सभ्यता का अभिन्न अंग रहे हैं। शिक्षा, साहित्य, प्रशासन और सामा. जिक मूल्यों में उनके योगदान ने एक स्थिर और तर्कसंगत प्रभाव प्रदान किया है जिससे पूरे समाज को लाभ हुआ है। उन्होंने सांस्कृ तिक और भाषाई मूल्यों के लगातार क्षरण पर चिंता व्यक्त की और कश्मीरी पंडित विरासत को संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि समुदाय के सांस्कृतिक, भाषाई और सभ्यतागत मूल्यों का संरक्षण कश्मीर की मिश्रित संस्कृति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जो कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरी है।

उच्च न्यायालय : गंभीर...

करते हुए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है। यह मामला पुलिस स्टेशन सदर, श्रीनगर में धारा 302, 307, 326, 324, 506, 201, 120-बी, 34 आरपीसी के तहत अपराधों के लिए एफआईआर संख्या 135/2012 से संबंधित है, जिसका मुकदमा श्रीनगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित है।”

अदालत ने आगे कहा कि निचली अदालत के बार-बार निर्देश देने के बावजूद अभियोजन पक्ष गवाहों की उपस्थिति दर्ज कराने में असमर्थ रहा है। जिन गवाहों के बयान अभी दर्ज किए जाने बाकी हैं, उनमें विशेषज्ञ और पुलिस अधिकारी शामिल हैं।

“इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां कुछ दीवानी गवाह, जिन्हें आरोपी ने अपने पक्ष में कर लिया हो, अभियोजन पक्ष के समर्थन में गवाही देने से बच रहे हों, बल्कि यह ऐसा मामला है जहां सरकारी गवाह भी मामले की शीघ्र सुनवाई में अभियोजन पक्ष की मदद करने से बच रहे हैं”, फ़ैसले में कहा गया है।

निचली अदालत के रिकॉर्ड को देखने से स्पष्ट है कि 33 गवाहों में से, अब तक निचली अदालत ने 13 साल से अधिक समय तक चले लंबे मुकदमे के दौरान 29 अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ की है और चार अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ अभी बाकी है।

न्यायमूर्ति धर ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने मुकदमे को पूरा करने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अथक प्रयास किए हैं, जिसके लिए निचली अदालत प्रशंसा की पात्र है। वास्तव में, एक गवाह से निचली अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ की है क्योंकि वह पंजाब में तैनात था।



भारतीय सेना के वीर जवानों की शौर्य गाथा

देश के वीर जवानों से जुड़ी कई कहानियाँ भी हैं जो न सिर्फ आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी, बल्कि उनकी कुर्बानियाँ आपकी आँखों को नम कर देंगी। वे फौलादी योद्धा हैं, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं। वे कड़ाके की ठंड और चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना हमेशा बहादुर, सजग और हमारे प्रति समर्पित रहते हैं। वे सभी नायक हैं, हर एक। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कहानियाँ किंवदंतियों का विषय बन गई हैं।

अभिनय आकाश

जब भी शांति की बात होती है, तो भारत का जिक्र सबसे पहले आता है। यही काम भारतीय सेना भी कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की शांति में भारतीय सेना का सबसे बड़ा योगदान रहा है। भारत इस बात के लिए भी जाना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के तहत स्थापित पहली महिला पुलिस अधिकारी भारत की ही थीं। क्या यह बहुत बड़ी बात नहीं है? अगर हम सेना की बात करें, तो सेना न सिर्फ देश की सुरक्षा में योगदान दे रही है, बल्कि देश के निर्माण और बुनियादी ढाँचे में भी उसका बड़ा योगदान है। देश के वीर जवानों से जुड़ी कई कहानियाँ भी हैं जो न सिर्फ आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी, बल्कि उनकी कुर्बानियाँ आपकी आँखों को नम कर देंगी। वे फौलादी योद्धा हैं, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं। वे कड़ाके की ठंड और चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना हमेशा बहादुर, सजग और हमारे प्रति समर्पित रहते हैं। वे सभी नायक हैं, हर एक। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कहानियाँ किंवदंतियों का विषय बन गई हैं।

1. कैप्टन विक्रम बत्रा

हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्मे, 13 जेएंडके राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध का नायक माना जाता है। उन्होंने कश्मीर में सबसे कठिन युद्ध अभियानों में से एक का नेतृत्व किया और उन्हें शेरशाह भी कहा गया। 17,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित चोटी 5140 पर पुनः कब्जा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस अभियान के दौरान, बत्रा गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने करीबी मुकाबले में तीन दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। चोटी 5140 पर कब्जा करने के बाद, वे 7 जुलाई, 1999 को चोटी 4875 पर पुनः कब्जा करने के लिए एक और कठिन अभियान पर निकल पड़े। बत्रा ने जाने से पहले अपने पिता को फोन किया और उन्हें इस महत्वपूर्ण अभियान के बारे में बताया। उन्हें शायद ही पता था कि यह घर पर उनका आखिरी फोन होगा। यह भारतीय सेना द्वारा किए गए सबसे कठिन अभियानों में से एक था क्योंकि पाकिस्तानी सेनाएँ चोटी से 16,000 फीट ऊपर बैठी थीं और चढ़ाई का ढलान 80 डिग्री था। ऊपर जाते समय, बत्रा का एक साथी अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया। बत्रा उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। जब एक सूबेदार ने उस अधिकारी को बचाने में उनकी मदद करने की कोशिश की, तो बत्रा ने उसे यह कहते हुए किनारे कर दिया, तुम्हारे बच्चे हैं, किनारे हट जाओ। उन्होंने अपने साथी सैनिक को तो बचा लिया, लेकिन दुश्मन के ठिकानों को साफ करते समय शहीद हो गए। बत्रा के अंतिम शब्द थे, जय माता दी।

2. मेजर जनरल इयान कार्डोजो

मेजर जनरल इयान कार्डोजो, जिनके नाम अनगिनत उपलब्धियाँ हैं, 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में उनके अदम्य साहस के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उस समय वे 5 गोरखा राइफल्स में एक युवा मेजर थे। युद्ध के दौरान, वे एक बारूदी सुरंग पर पैर रखकर गंभीर रूप से घायल हो गए। जब डॉक्टर भी उनका पैर नहीं काट पाए, तो कार्डोजो ने एक खुखरी (गोरखा चाकू) मँगवाई और अपना पैर यह कहते हुए काट दिया, अब जाओ और इसे दफना दो। इस घटना ने कार्डोजो को देश सेवा के लिए आगे बढ़ने से नहीं रोका। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के बल पर, उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन जारी रखा और भारतीय सेना में

एक पैदल सेना बटालियन और एक ब्रिगेड की कमान संभालने वाले पहले विकलांग अधिकारी बने। शारीरिक रूप से अन्य अधिकारियों के बराबर न होने के बावजूद, उन्होंने सेना में अपने कार्यकाल के दौरान कई फिटनेस परीक्षणों में कई शदो पैरों वाले सैनिकों को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया।

3. ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान

उत्तर प्रदेश के बीबीपुर में जन्मे, यह इस्पात पुरुष 1934 में भारतीय सेना में शामिल हुए। 1947/48 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान, ब्रिगेडियर उस्मान ने जम्मू और कश्मीर के दो अत्यधिक रणनीतिक स्थानों, नौशेरा और झांगर पर एक भीषण हमले को विफल कर दिया, और उनके साथी सैनिकों ने उन्हें शौशेरा का शेर नाम दिया। विभाजन के समय, उन्हें पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। उन्होंने पाकिस्तान की बलूच रेजिमेंट छोड़ दी और भारत में डोगरा रेजिमेंट में शामिल हो गए। नौशेरा की लड़ाई के बाद, जहाँ पाकिस्तानियों को उनके हाथों भारी क्षति हुई, उसी देश ने, जिसने उन्हें सेना प्रमुख बनने के लिए आमंत्रित किया था, अब आगे बढ़कर उन पर 50,000 रुपये का इनाम रख दिया। ब्रिगेडियर उस्मान न केवल एक वीर सैनिक थे, बल्कि एक दयालु व्यक्ति भी थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा और उनके पालन-पोषण के लिए दान कर देते थे। भारतीय सेना के इस प्रेरक और अनुकरणीय अधिकारी का 3 जुलाई, 1948 को झांगर की रक्षा करते हुए निधन हो गया।

4. सूबेदार योगेन्द्र सिंह यादव

इस वीर सैनिक को परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त है। उन्हें यह सम्मान 19 वर्ष की आयु में 4 जुलाई, 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए प्रदान किया गया था। 1980 में उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद अहीर गाँव में जन्मे यादव ने 1999 के युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने टाइगर हिल पर तीन रणनीतिक बंकरों पर कब्जा करने के कार्य के लिए स्वेच्छा से आगे आए, जो एक ऊर्ध्वाधर, बर्फ से ढकी, 16,500 फीट ऊँची चट्टान के शीर्ष पर स्थित थे। वह रस्सी के सहारे ऊँची चट्टान पर चढ़ रहे थे, तभी दुश्मन के बंकर से रॉकेट दागे जाने लगे। यादव की कमर और कंधे में तीन गोलियाँ लगीं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, यादव चढ़ते रहे और चट्टान की चोटी तक पहुँचने के लिए शेष 60 फीट की चढ़ाई पूरी की। अत्यधिक दर्द में होने के बावजूद, यादव रेंगते हुए पहले दुश्मन बंकर तक पहुँचे और एक ग्रेनेड फेंका, जिससे चार पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दुश्मन की गोलाबारी रुक गई। इससे शेष भारतीय पलटन को चट्टान पर चढ़ने का अवसर मिला। हालाँकि, बात यहीं खत्म नहीं हुई। यादव ने लड़ाई जारी रखी और दो साथी सैनिकों की मदद से दूसरे बंकर को भी तबाह कर दिया। दरअसल, उन्होंने दुश्मन के साथ आमने-सामने की लड़ाई भी लड़ी और चार और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।

5. राइफलमैन जसवंत सिंह रावत

इस वीर पुरुष की कहानी कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। 1962 के भारत-चीन युद्ध के नायक, चौथी गढ़वाल राइफल्स इन्फैंट्री रेजिमेंट के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, भारतीय सेना के इतिहास में एकमात्र ऐसे सैनिक हैं जो अपनी मृत्यु के बाद भी उच्च पदों पर पहुँचे। उनकी मृत्यु के 40 साल बाद उन्हें मेजर जनरल के पद पर श्पदोन्नत किया गया था, और माना जाता है कि आज भी वे चीन से लगती भारत की पूर्वी सीमाओं

की रक्षा करने वाले सैनिकों की श्रद्धान्जलि संभालते हैं। 1962 के युद्ध के दौरान, नूरानांग की लड़ाई में चीनियों के हाथों भारी क्षति के कारण सैनिकों को जल्द से जल्द अपनी चौकियाँ खाली करने का आदेश दिया गया था। लेकिन जसवंत ने अपनी जगह नहीं छोड़ी और अन्य सैनिकों के चले जाने के बाद भी लड़ते रहे। रावत की मदद सेला और नूरा नाम की दो मोनपा आदिवासी लड़कियों ने की। तीनों ने अलग-अलग जगहों पर हथियार तैनात किए और गोलीबारी की तीव्रता बनाए रखी ताकि चीनियों को लगे कि उनका सामना एक विशाल सेना से हो रहा है। रावत तीन दिनों तक उन्हें चकमा देने में कामयाब रहे। लेकिन चीनियों को इस योजना के बारे में एक ऐसे व्यक्ति के ज़रिए पता चल गया जो रावत और दोनों लड़कियों को राशन पहुँचाता था। रावत ने चीनी सेना द्वारा पकड़े जाने के बजाय खुद को गोली मारने का फैसला किया। यह जानकर कि वे इतने समय से एक ही सैनिक से लड़ रहे थे, चीनी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने रावत का सिर काटकर चीन वापस ले गए।

6. सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल

पुणे में जन्मे, 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट के द्वितीय लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल भी एक ऐसे ही वीर थे, जिनकी 21 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बसंतर की लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, जहाँ उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। खेत्रपाल ने दिसंबर 1971 में शकरगढ़ सेक्टर के जरपाल में, जब पाकिस्तानी बख्तरबंद गाड़ियों ने, जो ताकत में उनसे बेहतर थीं, जवाबी हमला किया, तो उन्होंने अदम्य साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया। हालाँकि खेत्रपाल एक अलग स्वप्नद्वारा में थे, फिर भी वे मदद के लिए दौड़ पड़े, दुश्मन की ओर बढ़े, अपने टैंकों से रक्षा पंक्ति को भेद दिया और पाकिस्तानी पैदल सेना और हथियारों पर कब्जा कर लिया। अपने सैनिकों के कमांडर के शहीद होने के बाद भी, खेत्रपाल ने दुश्मन पर तब तक भीषण हमला जारी रखा जब तक कि उनके टैंक पीछे हटने नहीं लगे। खेत्रपाल ने पीछे हटते हुए एक टैंक को भी नष्ट कर दिया।

लेकिन दुश्मन ने अपने कवच में सुधार किया और दूसरे हमले की तैयारी की। इस बार उन्होंने खेत्रपाल के कब्जे वाले क्षेत्र को निशाना बनाया। हमला जोरदार और तेज़ था। खेत्रपाल घायल हो गए, लेकिन दुश्मन के 10 टैंकों को नष्ट करने में कामयाब रहे। उन्हें अपना टैंक छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने इसे छोड़ दिया, तो दुश्मन अंदर घुस जाएगा। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुश्मन के एक और टैंक को नष्ट कर दिया। लेकिन तभी उनके अपने टैंक पर एक और हमला हुआ, जिसके परिणामस्वरूप इस साहसी अधिकारी की मृत्यु हो गई।

7. मेजर सोमनाथ शर्मा

चौथी कुमाऊँ रेजिमेंट के इस बहादुर सिपाही ने 24 साल की छोटी सी उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। हॉकी के एक खेल में लगी चोट के कारण उनके हाथ पर पहले से ही प्लास्टर चढ़ा हुआ था, फिर भी शर्मा ने 30 अक्टूबर, 1947 को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए जब अपनी कंपनी को हवाई मार्ग से श्रीनगर लाया गया, तो युद्ध में उनके साथ रहने की जिद की। 3 नवंबर को जब शर्मा की कंपनी बड़गाम गाँव में गश्त पर थी, तभी गुलमर्ग की ओर से 700 हमलावरों का एक कबायली लश्कर उन पर टूट पड़ा। कंपनी को जल्द ही तीन तरफ से घेर लिया गया और उसके

बाद हुई भारी मोर्तार बमबारी में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह महसूस करते हुए कि अगर वे इस समय युद्ध छोड़ देते हैं तो श्रीनगर और हवाई अड्डा असुरक्षित हो जाएगा, शर्मा एक चौकी से दूसरी चौकी तक दौड़ते रहे और अपने जवानों को एक ऐसे दुश्मन का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे जिसकी संख्या उनसे सात गुना ज्यादा थी। जब भारी क्षति ने उनकी मारक क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया, तो बाएँ हाथ पर प्लास्टर लगे शर्मा ने लाइट मशीन गन चलाने वालों के लिए मैगजीन भरने का काम शुरू कर दिया। जब वह लड़ाई में व्यस्त थे, तभी एक मोर्तार का गोला उनके पास रखे गोला-बारूद पर फट गया, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई।

8. नायक जदु नाथ सिंह

चौथे परमवीर चक्र विजेता नायक जदु नाथ सिंह ने 1947/48 के भारत-पाक युद्ध में जम्मू और कश्मीर में लड़ाई लड़ी थी। उनकी सूझबूझ और बहादुरी ने उनकी चौकी को एक बार नहीं, बल्कि तीन बार दुश्मन से बचाया। 6 फरवरी, 1948 के उस महत्वपूर्ण दिन, सिंह तैनात थे। उस चौकी पर नौ सैनिक तैनात थे। पाकिस्तानियों ने इस चौकी पर कब्जा करने के लिए लगातार हमले शुरू कर दिए। ऐसे समय में, सिंह ने शानदार नेतृत्व का परिचय दिया और अपनी छोटी सी सेना का इस तरह इस्तेमाल किया कि दुश्मन पूरी तरह से घबराकर पीछे हट गया। चार घायल सैनिकों के साथ, उन्होंने अपनी सेना को एक और हमले का सामना करने के लिए पुनर्गठित किया। संख्या में कम होने के बावजूद, उन्होंने हार नहीं मानी। जब उनके सभी सैनिक, जिनमें वे स्वयं भी शामिल थे, घायल हो गए, तो उन्होंने घायल गनर से ब्रेन गन ले ली और लड़ाई जारी रखी। दुश्मन अब चौकी की दीवारों पर थे, लेकिन सिंह की गोलाबारी इतनी विनाशकारी थी कि चौकी दूसरी बार भी बच गई। अब तक उनकी चौकी का हर व्यक्ति मर चुका था। पाकिस्तानी फिर से तीसरे हमले के लिए आए। घायल और अकेले, शर्मा अपनी स्टेन गन से फायरिंग करते हुए अपनी चौकी से बाहर निकले, जिससे दुश्मन दंग रह गया और उसे फिर से भ्रम में पड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन दो गोलियाँ शर्मा के सिर और सीने में लगीं और यह वीर सैनिक तुरंत शहीद हो गया।

9. सूबेदार करम सिंह

पंजाब के संगरूर जिले के सेहना गाँव में जन्मे करम सिंह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित नहीं किया गया। सिंह 1948 में भारतीय सेना से मानद कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए और 1993 में 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वे ब्रिटिश और भारतीय दोनों सरकारों के सर्वोच्च पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय भी हैं।

अपने कई बहादुरी भरे कार्यों के अलावा, करम सिंह को 13 अक्टूबर, 1948 को उनके साहस के लिए जाना जाता है, जब पाकिस्तान ने कश्मीर में रिश्मार गली पर फिर से कब्जा करने के लिए एक ब्रिगेड पर हमला करने का फैसला किया था। गोल. ीबारी इतनी भीषण थी कि भारतीय पलटन के लगभग सभी बंकर नष्ट हो गए। कमांडर के साथ संचार भी टूट गया और सिंह अपनी स्थिति की जानकारी नहीं दे सके या अतिरिक्त बल की माँग नहीं कर सके। दुश्मन के बहुत करीब आने पर भी उन्होंने चौकी खाली करने से इनकार कर दिया। जब दुश्मन सैनिक और भी करीब आ गए, तो करम सिंह अपनी खाई से कूद पड़े और दो घुसपैठियों को चाकू मारकर मार डाला।

एनसीएम ने भारत के इतिहास के युवा नायकों के अदम्य साहस, बलिदान और वीरता को सम्मानित एवं स्मरण करने के लिए वीर बाल दिवस का आयोजन किया

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) ने आज अपने कार्यालय परिसर में वीर बाल दिवस का आयोजन किया। इसका उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी को साहिबजादों के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के बारे में सूचित और शिक्षित करना था। साथ ही, भारत के इतिहास के युवा नायकों के अदम्य साहस, बलिदान और शौर्य का सम्मान और स्मरण करना भी था।

40 से अधिक बच्चों ने कहानी सुनाने, कविता पाठ, चित्रकारी, पोस्टर बनाने और वाद-विवाद जैसे कई रोचक और शिक्षाप्रद कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लिया। बच्चों ने स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत पर इसके प्रभावों पर निबंध लिखे।

इन कार्यकलापों ने बच्चों को अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने, भारत की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानने और वीरता, देशभक्ति और नैतिक शक्ति के मूल्यों को आत्मसात करने के लिए एक सार्थक मंच प्रदान किया।

एनसीएम की सचिव ने सभी प्रतिभागी बच्चों



के उत्साह और प्रयासों की सराहना की। विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए, जिससे युवा प्रतिभागियों के बीच उत्कृष्टता और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला। उन्होंने अपने समापन भाषण में कहा कि देश के बच्चों और युवाओं को प्रधानमंत्री के उस आह्वान का पालन करना चाहिए जिसमें उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित करने की बात कही है।

यह आयोजन वास्तव में प्रधानमंत्री की वीर बाल दिवस मनाने की अपील भावना को

दर्शाता है। इसमें भारत के बच्चों की रचनात्मकता, आकांक्षाओं और क्षमता को प्रदर्शित किया गया, जो राष्ट्र के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन श्कोप फॉर चेंज के सहयोग से किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इन पहलों के माध्यम से सभी समुदायों के बच्चों के बीच समावेशी भागीदारी, ऐतिहासिक जागरूकता और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में 24.12.2025 को सुश्री रचना शाह, सचिव, विभागाध्यक्ष और लोकपाल कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में 15वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया गया

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डाक मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 30 विभागों/मंत्रालयों से संबंधित अति वरिष्ठ और पारिवारिक पेंशनभोगियों की 1087 शिकायतों को अदालत में निवारण के लिए लाया गया। इनमें से 815 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। यह पेंशनभोगियों को समय पर न्याय दिलाने में इस पहल की दक्षता को रेखांकित करता है।

24.12.2025 को आयोजित अदालत से कई प्रेरणादायक सफलता की कहानियां सामने आईं। पेंशनभोगियों द्वारा झेली गई कठिनाइयों को समझने और पेंशन अदालत की व्यवस्था के माध्यम से उन्हें उनके लंबे समय से लंबित हक प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ मामलों के अंश नीचे दिए गए हैं।

श्री प्रीतम सिंह

हरियाणा के रेवाड़ी निवासी श्री प्रीतम सिंह की शिकायत 114 दिनों से अधिक समय से लंबित थी। यह शिकायत जीपीएफ, अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी के भुगतान न होने से संबंधित थी। उन्होंने फोन पर अपनी शिकायत के लंबित होने के बारे में चिंता व्यक्त की। बीएसएफ के अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया

कि मामला सुलझा लिया गया है और पेंशनभोगी के खाते में 68,10,192 रुपये की कुल बकाया राशि जल्द से जल्द जमा कर दी जाएगी।

श्री केवल कृष्ण

जम्मू-कश्मीर निवासी श्री केवल कृष्ण की शिकायत 150 दिनों से अधिक समय से लंबित थी। यह शिकायत उनकी पत्नी श्रीमती फोली देवी के निधन के बाद पारिवारिक पेंशन के शुरू होने में हुई देरी से संबंधित थी। श्रीमती फोली देवी को उनके पुत्र, सीआरपीएफ में कार्यरत सीटी/जीडी नरेश कुमार के निधन के बाद स्वीकृत पारिवारिक पेंशन मिल रही थी। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने सूचित किया कि अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के रूप में 8,56,107 रुपये की राशि जमा कर दी गई है और 12 जुलाई 2020 से 30 नवंबर 2025 तक का कुल बकाया 12,11,444 रुपये का भुगतान शीघ्र ही किया जाएगा।

उत्तराखंड निवासी श्रीमती खिमली देवी पारिवारिक पेंशनभोगी हैं। इनके पति एसएसबी में तैनात थे। उनकी शिकायत 133 दिनों से अधिक पुरानी थी। वे न्यूनतम असाधारण पेंशन के संशोधन और ब्याज सहित बकाया राशि के भुगतान की प्रतीक्षा कर रही थीं। उनकी शिकायत 150 दिनों से अधिक समय से लंबित थी। उनकी शिकायत न्यूनतम असाधारण पेंशन के संशोधन पर ब्याज सहित बकाया राशि के

भुगतान से संबंधित थी। उनके पोते ने वीडियो कॉल के माध्यम से बताया कि अतिरिक्त पेंशन का बकाया भुगतान नहीं किया गया है और उन्होंने पूरी बकाया राशि की गणना शीट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। एसएसबी के नोडल अधिकारी ने आश्वासन दिया कि शेष बकाया राशि का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा और गणना शीट भी उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्रीमती सबित्री बाग स्वर्गीय श्री क्षमा सिल बाग की विधवा हैं, जो डाक विभाग से सेवा निवृत्त हुए थे। उनकी शिकायत 129 दिनों से अधिक समय से लंबित थी। दिवंगत अधिकारी के निलंबन की अवधि को नियमित करने में देरी हुई। इसके परिणामस्वरूप 8 सितंबर 2024 को उनकी मृत्यु के बाद भी वेतन लाभ जारी नहीं किया गया और पारिवारिक पेंशन से वंचित रखा गया।

उनके पुत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में शामिल हुए। डाक विभाग द्वारा सूचित किया गया कि स्वर्गीय श्री क्षमा सिल बाग की सेवा अवधि 11 अक्टूबर 2014 से 9 जनवरी 2020 तक 21 नवंबर 2025 को नियमित कर दी गई है। हालांकि अदालत कहा कि पारिवारिक पेंशनभोगी को सेवानिवृत्ति लाभों की बकाया राशि का भुगतान शीघ्रता से करने के लिए एक सप्ताह के भीतर मामले की अनुवर्ती कार्रवाई की जानी है।

मूलभूत सभ्यतागत मूल्यों को संरक्षित रखते हुए और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर भारत ने परंपरा के साथ आधुनिकता को सफलतापूर्वक जोड़ा है : डॉ. जितेंद्र सिंह

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आज आयोजित भारतीय विज्ञान सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने मूलभूत सभ्यतागत मूल्यों को संरक्षित करते हुए और साथ ही अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर परंपरा के साथ आधुनिकता को सफलतापूर्वक जोड़ा है, जिसका अंतिम लक्ष्य आम नागरिक के लिए जीवन को सुगम बनाना है। मंत्री महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत का वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में उभर कर सामने आना शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व द्वारा प्रदान किए गए निर्णायक नीतिगत समर्थन के कारण संभव हो पाया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले एक दशक में, विशेषकर 2014 से, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को अभूतपूर्व नीतिगत प्राथमिकता और बजटीय समर्थन में मिला है, जिससे उन दीर्घकालिक बाधाओं को दूर किया गया है जो पहले भारत की वैज्ञानिक क्षमता को सीमित करती थीं। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा की कमी कमी नहीं थी, बल्कि सक्षम इकोसिस्टम और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव था, जिसे अब निर्णायक रूप से दूर कर दिया गया है। भारत में नवाचार की तीव्र प्रगति पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में लगभग 300-400 से बढ़कर आज लगभग दो लाख हो गई है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो गया है। उन्होंने बताया कि वैश्विक नवाच. 17 सूचकांक में भारत की रैंकिंग 81 से सुधरकर 38 हो गई है, जबकि पेटेंट दाखिल करने के मामले में भारत अब विश्व में छठे स्थान पर है, जिसमें आधे से अधिक पेटेंट रजिस्टर्ड इंडियन्स द्वारा दाखिल किए जा रहे हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में भारत की उपलब्धियों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने देश के चंद्र अभियानों का उदाहरण दिया, जिनसे चंद्रमा पर पानी की पहली पुष्ट उपस्थिति का प्रमाण मिला और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट विश्व की पहली लैंडिंग हुई। उन्होंने भारत के स्वदेशी रक्षा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती पर भी प्रकाश डाला और बताया कि रक्षा निर्यात 23,662 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसमें लगभग 100 देशों भारतीय निर्मित प्रणालियों की आपूर्ति की जा रही है। हाल के वैश्विक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की स्वदेशी मिसाइल और रक्षा प्रौद्योगिकियों ने अपनी विश्वसनीयता और भरोसे को प्रदर्शित किया है, जिसके कारण इनकी अंतरराष्ट्रीय मांग बढ़ रही है। उन्होंने रेखांकित किया कि ये क्षमताएं पिछले एक दशक में परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और उन्नत अनुसंधान में किए गए निरंतर निवेश का परिणाम हैं। स्वास्थ्य सेवा के संबंध में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत निवारक स्वास्थ्य सेवा और किफायती चिकित्सा समाधानों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में उभरा है। कोविड-19 टीकों के विकास और उन्हें दुनिया के साथ साझा करने से लेकर प्रतिवर्ष अरबों डॉलर के चिकित्सा उपकरणों और प्रत्यारोपणों के निर्यात तक भारत के स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वास और मान्यता प्राप्त की है।

मंत्री महोदय ने वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रकाशनों में भारत के बढ़ते प्रभाव पर भी प्रकाश डाला और कहा कि वैज्ञानिक शोध पत्रों के आउटपुट में देश अब वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है और उद्घरण इम्पैक्ट में तीसरे स्थान पर है, जो अनुसंधान में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की प्रगति को दर्शाता है।

कश्मीरियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर महबूबा ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री से राज्यों में मंत्रिस्तरीय दल भेजने का आग्रह किया

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर, 26 दिसंबर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है और उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उत्पीड़न की घटनाओं के मद्देनजर वहां कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों में मंत्री स्तरीय टीम भेजी जाए

। महबूबा ने यहां पत्रकारों से कहा, "पूरे देश में असहिष्णुता बढ़ गई है।

लिंगिंग की घटनाएं हो रही हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है, उससे हमें दुख होता है, लेकिन जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, वे यहां लिंगिंग होते देख मूक दर्शक बने रहते हैं।"

उत्तराखंड में एक कश्मीरी व्यापारी पर हुए हमले का जिक्र करते हुए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)

प्रमुख ने कहा कि उन्होंने तुरंत एक ट्वीट किया और उत्तराखंड के डीजीपी को टैग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की।

उन्होंने आगे कहा, "इसीलिए आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस में अभी भी कुछ अधिकारी हैं जो कार्रवाई करते हैं। लेकिन 72 घंटों में तीन घटनाएं हुई? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में। जो हो

रहा है वह चिंताजनक है।" उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आग्रह किया कि वे एक मंत्री स्तरीय टीम गठित करें और उसे राज्यों में भेजें ताकि वहां कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। "हमारी सरकार को हर राज्य में, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में, जहां इस तरह की ज्यादातर घटनाएं होती हैं, मंत्रिस्तरीय टीम भेजनी चाहिए," उन्होंने कहा।

आरएसएस नेटवर्क का खुलासा

(आलेख : सवेरा, अनुवाद : संजय पराते)

पहली बार, शोधकर्ताओं ने आरएसएस से जुड़े संगठनों के रहस्यमयी नेटवर्क की तस्वीर सामने लाने के लिए सबूत इकट्ठा किए हैं — और नतीजा परेशान करने वाला है। उन्होंने उन 2500 संगठनों के एक नेटवर्क का पता लगाया है, जिन्हें संघ से वैचारिक, संगठनात्मक और अक्सर आर्थिक मदद मिलती है। इन 2500 संगठनों में से 2240 भारत में हैं, जबकि बाकी 39 देशों में फैले हुए हैं। उन्होंने यह भी मानचित्र बनाया है कि ये संगठन एक-दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, जिससे मातृ संगठन आरएसएस से उनके बहुस्तरीय संबंध सामने आए हैं। सामाजिक सेवा या धार्मिक-सांस्कृतिक संगठनों के इस विशाल नेटवर्क के जरिए ही आरएसएस अपनी हिंदुत्व की जहरीली विचारधारा फैलाता है। इस तस्वीर को एक साथ जोड़ने में छह साल लंबा समय लगा। यह काम पेरिस के एकेडेमिक संस्थान सेरी-साइंसेज पो और दिल्ली की मैगजीन द कारवां के शोधकर्ताओं ने किया। नेटवर्क में हर संगठन के स्थान और अन्य विवरण दिखाने वाला एक परस्पर संवादात्मक मानचित्र कारवां की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें एक नेटवर्क प्रतिचित्रण (मैपिंग) भी है, जो इन संगठनों के एक-दूसरे के साथ संबंध दिखाती है। कार्यप्रणाली का विवरण और मुख्य लेखक फेलिक्स पाल का एक लेख भी ऑनलाइन उपलब्ध है।

मानचित्र में भारत पर जूम करने पर पता चलता है कि किन-किन राज्यों में आरएसएस से जुड़े ऐसे कितने संगठन हैं। ऐसे संगठनों वाले कुछ बड़े राज्य हैं रु उत्तर प्रदेश दृ 280 ; महाराष्ट्र दृ 259 ; कर्नाटक - 174 ; गुजरात - 136 ; केरल दृ 212 ; मध्य प्रदेश दृ 73 ; पश्चिम बंगाल दृ 75 ; तमिलनाडु दृ 76। जम्मू-कश्मीर में ऐसे 55 संगठन हैं, जबकि उत्तर-पूर्व के आठ राज्यों में कुल 75 संगठन हैं, जिनमें से अकेले असम में 44 हैं। ये संख्याएँ शायद ऐतिहासिक विरासत को दिखाती हैं दृ जैसे उत्तरप्रदेश या महाराष्ट्र या उत्तर-पूर्व में, जहाँ आरएसएस दशकों से सक्रिय है, या फिर ये पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में हाल की प्राथमिकताओं को दिखाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मोटे तौर पर कहे तो, आरएसएस का नेटवर्क पुराने और नए, दोनों तरह के प्रवासी भारतीयों के बीच फैला हुआ है। द कारवां की शोध के अनुसार, उदाहरण के लिए, कैरिबियन या मॉरीशस या फिजी, या दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे ऐतिहासिक प्रवासी हिंदू आबादी वाले ज्यादातर छोटे देशों में हिंदू समुदायों में आरएसएस के मोर्चे सक्रिय हैं, हालांकि इन आंकड़ों से उनके पैमाने या प्रभाव का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आरएसएस से जुड़े संगठनों का सबसे बड़ा जमावड़ा अमेरिका (107) में पाया जाता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया (34) और यूनाइटेड किंगडम (26) का नंबर आता है। नेटवर्क मानचित्रण से यह संकेत मिलता है कि आरएसएस से जुड़े ये विदेश-आधारित संगठन अक्सर भारत-आधारित संगठनों के लिए वित्त पोषण (फंडिंग) का स्रोत होते हैं। उदाहरण के लिए, इंडिया डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड (आईडीआरएफ) अमेरिका में मैरीलैंड-स्थित एक कर-छूट प्राप्त, गैर-लाभकारी संगठन है। यह भारत में आरएसएस के कई संगठनों के लिए वित्त पोषण का एक मुख्य स्रोत है। श्रृंखला मानचित्रण से पता चलता है कि यह कम से कम 200 संगठनों से जुड़ा हुआ है, जिसमें सेवा भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), वनवासी कल्याण आश्रम (वीकेए) जैसे बड़े संगठन शामिल हैं, लेकिन साथ ही देश भर में फैले छोटे एनजीओ-प्रकार के संगठनों का एक समूह भी है। इसी तरह, सपोर्ट ए चाइल्ड, यूएसए एक और संगठन है, जो संभावित रूप से भारत में आरएसएस-समर्थित संगठनों का वित्त पोषण करता है। यह सीधे विश्व हिंदू परिषद, यूएसए से जुड़ा हुआ है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन कई देशों में काम कर रहे हैं। उनमें से एक ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीज. पी है, जिसकी कई प्रमुख देशों में शाखाएँ हैं। इसी तरह, विश्व हिंदू परिषद की विभिन्न देशों में सीधी



सहायक संस्थाएँ हैं। आरएसएस का खुद का एक विदेशी मोर्चा है, जिसे हिंदू स्वयंसेवक संघ कहा जाता है। इसकी अधिकांश देशों में शाखाएँ हैं, जहाँ सहयोगी संगठन काम कर रहे हैं।

आरएसएस से जुड़े विदेश-आधारित ज्यादातर संगठन सामुदायिक संगठनों के रूप में काम करते हैं, धार्मिक त्योहार मनाते हैं, कुछ सामुदायिक सेवाएँ चलाते हैं और भारत से आने वाले नेताओं की मेज़बानी करते हैं। इनमें से कुछ, जैसा कि पहले बताया गया है, मुख्य रूप से जिस देश में वे हैं, वहाँ दानदाताओं से फंड इकट्ठा करते हैं और उसे भारत में अलग-अलग संगठनों को भेजते हैं।

ये भारत-आधारित संगठन क्या काम करते हैं?

ये संगठन कई तरह के मुद्दे उठाते हैं और उन पर काम करते हैं, जैसे रु सेवाएँ देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, आर्थिक, रक्षा/सुरक्षा, धार्मिक गतिविधियाँ, श्रम, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मामले, वगैरह। फिर, कई संगठन ऐसे हैं, जो व्यवसाय पर आधारित हैं दृ व्यापारी, डॉक्टर, वकील, पूर्व सैनिक, शिक्षक, वगैरह। ये छोटे एनजीओ से लेकर धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट, सहकारिताएँ, सामाजिक संस्थाएँ या सिर्फ व्यक्तियों के संगठन हैं, जिनका कोई पंजीयन नहीं है। ये संगठन अपनी सामान्य गतिविधियों के जरिए ज़रूरतमंद लोगों को आरएसएस की ओर आकर्षित करते हैं।

आरएसएस सार्वजनिक तौर पर सिर्फ 32 सहयोगी संगठनों को मान्यता देता है, या जैसा कि वे कहते हैं, ये संघ से प्रेरित संगठन हैं। इनमें भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती, सेवा भारती, एबीवीपी आदि जैसे सभी बड़े संगठन शामिल हैं। इनके साथ नियमित रूप से समन्वय बैठकें होती हैं, और इनके पदाधिकारी आरएसएस की सर्वोच्च सलाह देने वाली संस्था, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (प्रतिनिधियों के अखिल भारतीय सम्मेलन) के सदस्य होते हैं।

लेकिन बाकी 2000 से ज्यादा संगठनों का आधिकारिक तौर पर शायद ही कभी जिक्र किया जाता है, सिवाय आम शब्दों में, जैसे श्मसान सोच वाले संगठन या श्मज्जन समाज। मातृ संगठन से इनका संबंध या लिंक आरएसएस सदस्यों (स्वयंसेवकों) या प्रचारकों (आरएसएस के पूरा-वक्ती कार्यकर्ताओं) के जरिए होता है। इन संगठनों का मुख्य मकसद आरएसएस के मुख्य वैचारिक संदेशों को उन लोगों तक पहुँचाना है, जिन पर उनका असर होता है। इन मुख्य विचारों में शामिल हैं रु हिंदू समाज को जगाना और उसके श्मानदार अतीत के बारे में बताकर उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करना ; सनातन धर्म से निकली अलग-अलग रस्मों, रीति-रिवाजों, परंपराओं और मौकों को अपनाना और उनका पालन करना ; हिंदू समाज के सामने आने वाले खतरों और जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करना ; और आखिरकार, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की दिशा में काम करना। जाहिर है, इन मुख्य संदेशों को हर संगठन जिस लक्षित आबादी के साथ काम कर रहा है, उसके हिसाब से ढालना और समझाना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, विद्या भारती 15,000 से ज्यादा औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त स्कूल, आदिवासी इलाकों में लगभग 4000 एकल शिक्षा केंद्र (अनौपचारिक एकल शिक्षक केंद्र), गरीब शहरी इलाकों में लगभग 5000 संस्कार केंद्र और 60

कॉलेज चलाती है। इन सभी में, श्मैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा एक मुख्य हिस्सा है — जिसे हिंदुत्व विचारधारा की जगह नाम दिया गया है। संयोग से, इन स्कूलों को द कारवां ने आरएसएस नेटवर्क में नहीं गिना है। एकल शिक्षा केंद्र आदिवासी इलाकों में काम करता है। यह आरएसएस से प्रेरित एक अन्य बड़े संगठन, वनवासी कल्याण आश्रम (वीकेए) की गतिविधियों के साथ ओवरलैप करता है। वनवासी कल्याण आश्रम के खुद दर्जनों सहयोगी संगठन हैं, जो स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से काम करते हैं — उदाहरण के लिए, इसके उत्तर-पूर्वी राज्यों में से हर एक में अलग-अलग मोर्चे हैं, और मध्य भारतीय आदिवासी इलाकों में अलग हैं। इन मोर्चों द्वारा आदिवासियों के बीच बेहतर स्वीकार्यता बनाने के लिए स्थानीय मान्यताओं और रीति-रिवाजों को अपनाया जाता है। पेशागत संगठन भी इसी तरह का तरीका अपनाते हैं। अपने सदस्यों के हितों के लिए लॉबींग करते हुए वे आरएसएस और भाजपा की वैचारिक लाइनों के साथ विभिन्न मुद्दों पर तालमेल बिठाते हैं। काम करने की ओवरलैपिंग और फेडरेंटिंग (पारस्परिक व्याप्ति और एक संस्था में केंद्रीभूत) शैली एक साफ़ खासियत है, जो ज्यादातर लोगों की नजर से ओझल रहती है। इस शोध के मुख्य लेखक फेलिक्स पाल ने मानचित्र और आंकड़ों के साथ अपने निबंध में बताया है कि आरएसएस के 46 श्रमांतोर् (राज्यों) में से हर एक में संघ से जुड़े मुख्य संगठनों के अपने-अपने रूप हैं रु विद्या भारती पंजाब में सर्वहितकारी शिक्षा समिति बन जाती है ; सेवा भारती कर्नाटक में हिंदू सेवा प्रतिष्ठान बन जाती है ; और वनवासी कल्याण आश्रम झारखंड में वनवासी कल्याण केंद्र बन जाता है। फेलिक्स पाल ने जम्मू में 20 संगठनों का उदाहरण दिया है, जो सभी वेद मंदिर में स्थित एक ही परिसर से चलाए जाते हैं। यह ज़मीन 1916 में डोगरा शासक ने एक व्यक्ति को वैदिक मंदिर बनाने के लिए दी थी। 1964 में वेद मंदिर कमेटी रजिस्टर हुई। पाल लिखते हैं कि बाद में इसे आरएसएस ने अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ से चलने वाले संगठनों में शामिल हैं दृ बुजुर्गों और कमजोर लोगों के लिए एक आवास, एक गौशाला, एक पूजा स्थल, बीमारियों के प्राकृतिक इलाज का एक केंद्र, कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिकों के लिए एक एनजीओ, कटरा में एक छात्रावास, लड़के और लड़कियों के लिए अनाथालय, एक स्कूल, एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, एक अस्पताल, तीर्थयात्रियों के लिए एक लॉज, वेदों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल और आरएसएस से जुड़े आधे दर्जन संगठनों के दफ्तर। वेद मंदिर बाल निकेतन के सभी चार पदाधिकारी आरएसएस के लोग हैं, और वे इस क्षेत्र के कई अन्य आरएसएस से जुड़े संगठनों के नेता भी हैं। असल में, अध्यक्ष आरएसएस के जम्मू प्रांत के संघचालक (प्रमुख) हैं। मंदिर परिसर से काम करने वाली कुछ संस्थाओं को अमेरिका और कनाडा में स्थित आईडीआरएफ और सेवा इंटरनेशनल से फंड मिलता है। जम्मू मंदिर परिसर पूरे आरएसएस नेटवर्क का एक छोटा-सा रूप है। इतना ज्यादा छोटा कि जब भी आरएसएस सरसंघचालक (सुप्रीम) इस क्षेत्र में आते हैं, तो वे हमेशा वहीं रुकते हैं।

यह तो बस शुरुआत है

शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आरएसएस के नेटवर्क की पूरी तस्वीर नहीं है। उनका ज्यादातर काम ऑनलाइन शोध पर आधारित है और जाहिर है, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, जो अपनी जानकारी ऑनलाइन नहीं देते हैं। इसके अलावा, शोध में जानबूझकर कुछ पहलुओं को छोड़ दिया गया है, जैसे कि उनसे जुड़े स्कूल, जिनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि वे दूसरे संगठनों को श्पीछे छोड़ सकते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि स्कूल, बालवाड़ी और सांस्कृतिक केंद्र आदि आरएसएस के लिए कम ज़रूरी हैं। असल में, लोगों को अपनी पिछड़ी सोच में ढालने की आरएसएस की कोशिशों में ये शायद सबसे श्मफलर हैं।

मोदी के ग्यारह साल के शासन में, आरएसएस की अलग-अलग गतिविधियों जैसे चरित्र निर्माण के लिए कार्यशाला, सांस्कृतिक जागरूकता या प्राचीन विज्ञान के लिए सेमिनार और सम्मेलन वगैरह के लिए सरकार की मदद दृ इसे वित्त पोषण पढ़ें दृ बड़े पैमाने पर बढ़ी है। इस प्रक्रिया में, कई संगठन सामने आए हैं या मौजूदा संगठनों को अपनी गतिविधियों के लिए बढ़ावा मिला है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हो सकता है कि यह डेटाबेस में दिखाई न दे। दूसरे तरह के संगठन, जिन्हें मोदी के ज़माने में बढ़ावा मिला है, वे हैं अलग-अलग हिंदुत्व उग्रवादी संगठन, जो श्मौ-रक्षा गतिविधियां कर रहे हैं या त्योहारों और दूसरी ऐसी ही गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। हो सकता है कि इनका कोई पक्का सांगठनिक ढांचा न हो और समय के साथ ये कुछ ज्यादा स्थायी रूप ले लें। ये भी ज्यादातर डेटाबेस में शामिल नहीं हैं। संगठनों की एक और श्रेणी नए मीडिया-आधारित नेटवर्क हैं दृ यू-ट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल, आदि। संगठनात्मक नज़रिए से यह एक ग्रे एरिया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे हजारों नेटवर्क हैं, जो सक्रिय रूप से संघ की विचारधारा फैला रहे हैं और संघ के सदस्यों द्वारा प्रबंधित किए जा रहे हैं। ये भी इस डेटाबेस में शायद ही शामिल हैं।

और, आखिर में, जैसा कि शोधकर्ता खुद ज़ोर देते हैं, ये आंकड़े सिर्फ आरएसएस नेटवर्क का हैं, न कि हिंदुत्व से जुड़े सभी संगठनों का। यह संभव है कि आरएसएस प्रचारक की अगुवाई वाली सरकार होने की वजह से, आरएसएस से जुड़े संगठन एक जैसी विचारधारा वाले, लेकिन अलग-अलग संगठनात्मक मूल वाले, दूसरे सभी संगठनों पर हावी रहेंगे। लेकिन अभी तक, ऐसे कई संगठन डेटाबेस में शामिल नहीं होंगे। लड़ाई जारी है यह ज़ोर देकर कहना ज़रूरी है कि इस विशाल नेटवर्क के बावजूद दृ जो फैला हुआ है और एक-दूसरे से जुड़ा हुआ भी है दृ आरएसएस की विचारधारा और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसकी संगठनात्मक पकड़, पूरे देश में असमान रूप से फैली हुई है। इसके बड़े हिस्से ऐसे हैं, जहाँ यह सिर्फ ऊपरी तौर पर ही पहुँचा है। आरएसएस के प्रभाव का अंदाज़ा न तो उसके बनाए संगठनों की संख्या से लगाया जा सकता है और न ही भाजपा की वोटों में हिस्सेदारी से। इन संगठनों से जुड़े लोग कई वजहों से इसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं और उन्हें आरएसएस का अनुयायी नहीं माना जा सकता। संगठनों का एक-दूसरे से जुड़ा होना भी उनके प्रभाव के एक-दूसरे से जुड़े आधारों को दिखाता है।

इसी तरह, भाजपा को मिलने वाले वोट अलग-अलग इलाकों और क्षेत्रों में, और यहाँ तक कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव में भी बहुत अलग-अलग होते हैं। आरएसएस अपने मोर्चा संगठनों — खासकर मौजूदा दौर में भाजपा — का सहारा लेकर वह हासिल करना चाहता है, जो वह एक सदी में भी नहीं कर पाया। वह कितना सफल होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतें उसे कितनी चुनौती देती हैं। ये ताकतें अभी भी भारत की ज्यादातर आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क रु 94242-31650)

‘गाजीपुर डेरीफॉर्म दिल्ली -96’ में पाँच अवैध मस्जिदनुमा ढाँचे : कानून, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खुली चुनौती

एमसीडी सूत्रों के दावे से हड़कंप कृ गाजीपुर थाने के करीब सरकारी जमीन पर कब्जा, फिर भी कार्रवाई शून्य? डॉक्यूमेंट्स के बिना निर्माण, फर्जी पहचान और तब्लीगी जमात की आवाजाही - गाजीपुर मंडी बना राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी का प्रतीक

रविंद्र आर्य

दिल्ली बॉर्डर / गाजियाबाद : गाजियाबाद सीमा पर स्थित गाजीपुर मुर्गा, बैस और बकरा मंडी क्षेत्र में वर्षों से पनप रहा एक गंभीर प्रशासनिक, धार्मिक भूमि-कब्जा और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला अब खुलकर सामने आया है। स्थल पर स्वयं जाकर किए गए सर्वे, स्थानीय नागरिकों, मंडी कर्मियों और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के वरिष्ठ अधिकारियों से हुई बातचीत तथा उपलब्ध वीडियो-फोटो साक्ष्यों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों, अवैध कब्जों, आंतरिक सुरक्षा, प्रशासनिक विफलताओं और जमीनी सच्चाइयों पर आधारित रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले वरिष्ठ खोजी पत्रकार एवं लेखक रविंद्र आर्य की यह रिपोर्ट प्रत्यक्ष अवलोकन और दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है।

जिस रिपोर्ट में यह तथ्य स्पष्ट होता है कि गाजीपुर मंडी के शुरुआती दौर में, लगभग वर्ष 2009 के आसपास, गाजीपुर डेरीफॉर्म दिल्ली-96 क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम द्वारा केवल एक मस्जिद (जामिया मस्जिद) और एक मंदिर की अनुमति दी गई थी। आज स्थिति यह है कि मंदिर अब भी एक ही है, किंतु मस्जिद के नाम पर एक के बाद एक पाँच अवैध मस्जिदनुमा ढाँचे बिना किसी वैध नक्शे, दस्तावेज, भूमि अधिकार या प्रशासनिक स्वीकृति के खड़े कर दिए गए हैं और वर्षों से संचालित भी हैं।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा अवैध निर्माण गाजीपुर थाना से बेहद नजदीक है। इसके आसपास ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों की सैकड़ों झुग्गी-झोपड़ियाँ सरकारी जमीन और मंडी परिसर के भीतर विकसित हो चुकी हैं। ठीक सामने डीडीए के ए, बी, सी और डी ब्लॉक डेरीफॉर्म फ्लैट्स हैं और उनके आसपास मंडी से लेकर बाहरी क्षेत्रों तक सरकारी भूमि पर लगातार अवैध मस्जिदों का निर्माण होता चला गया, जबकि प्रशासन दावा करता रहा कि उसे इसकी “जानकारी तक नहीं” थी।

‘स्थानीय डेरीफॉर्म निवासियों की गुप्त शिकायत और एमसीडी की आंशिक कार्रवाई’

स्थानीय डेरीफॉर्म निवासियों ने दो वर्ष पूर्व दिल्ली नगर निगम को गुप्त शिकायत दी थी कि सरकारी जमीन पर जामिया मस्जिद के पीछे अवैध विस्तार किया जा रहा है। एमसीडी सूत्रों के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर अवैध मस्जिद के पीछे बनाए जा रहे बड़े हॉल और कमरे को नींव से लेकर लैंटर तक बनाया जा रहा था, जिसको एमसीडी ने ध्वस्त किया। लेकिन मूल मस्जिदनुमा ढाँचा और उससे जुड़े अन्य चार अवैध मस्जिदों पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बिना किसी नक्शे या दस्तावेज के बने इन धार्मिक ढाँचों, टीनशेड और स्टाफ रुमनुमा कमरों को धार्मिक गतिविधियों के नाम पर अछूता छोड़ दिया गया है। जहाँ आज भी नमाजे पढ़ने के टाइमिंग बोर्ड खुलेआम लगे हैं।

‘मंडी परिसर के भीतर खुले धार्मिक गतिविधियाँ और तब्लीगी जमात’ रिपोर्टिंग के दौरान यह भी पाया गया कि बकरा मंडी और बैस मंडी परिसर के भीतर अस्थायी स्टॉफ कमरों में उसके बहार टीनशेड में आज भी टाइमिंग बोर्ड लगाकर नमाज अदा की जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ लंबे समय से तब्लीगी जमातों का ठहराव और आना-जाना लगा रहता है। प्रारंभिक रूप से लगभग 15x15 फीट का ढाँचा अब पाँच अवैध मस्जिदों और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र में तब्दील हो चुका है।

इन अवैध ढाँचों पर बाकायदा उर्दू और अंग्रेजी में बोर्ड लगाए गए हैं कृ

‘श्रृंखला में पंचनत वंशतल थंतल क्मसीप-96’।

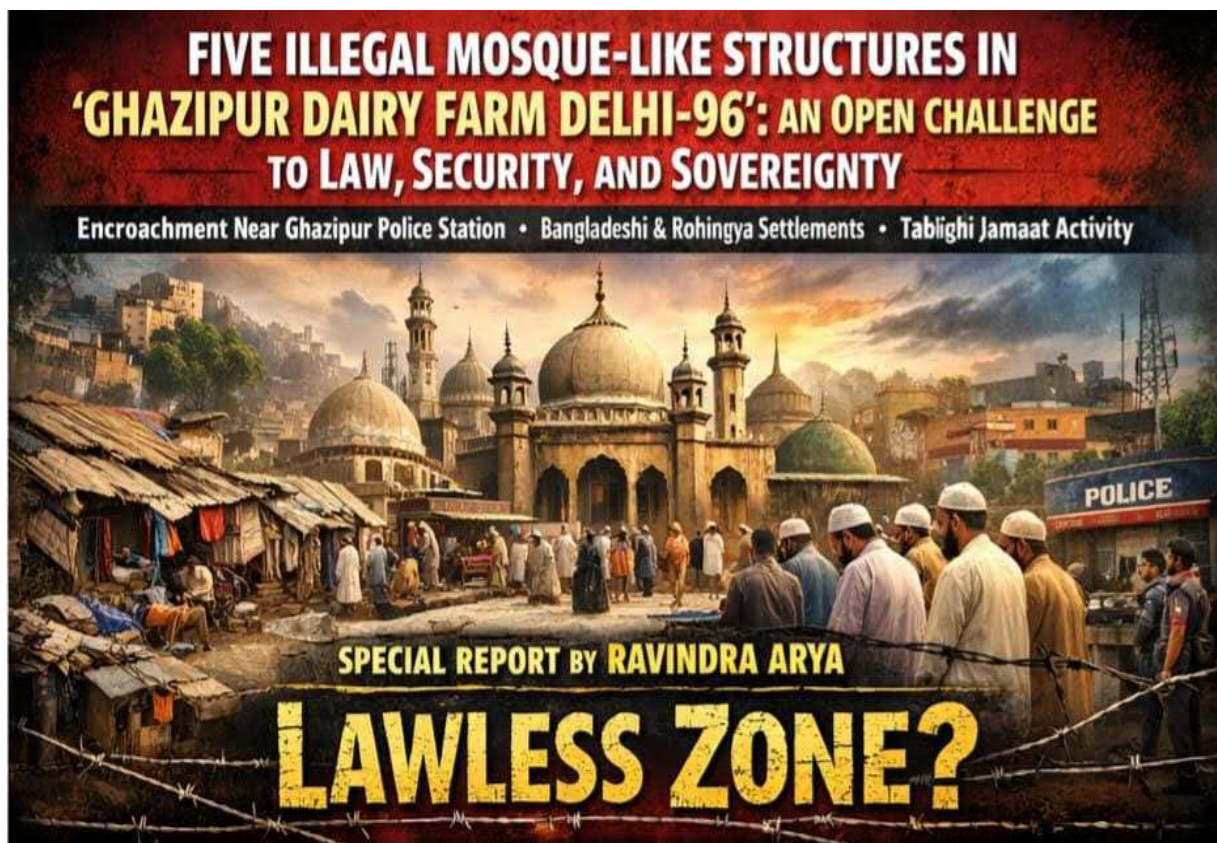
जानबूझकर न लाउडस्पीकर लगाए गए, न औपचारिक मस्जिद जैसा स्वरूप दिया गया, ताकि अवैध कब्जा, तब्लीगी गतिविधियाँ और बांग्लादेशी-रोहिंग्या नेटवर्क प्रशासन की नज़र से बचा रहे।

‘बांग्लादेशी-रोहिंग्या नेटवर्क ने फंड इकट्ठा कर गाजीपुर मुर्गा मंडी में अवैध मस्जिद बना डाली’

इसी के सामने और पीछे सरकारी जमीन पर अनेकों कब्जे और झोपड़ी-नुमा ‘भूरा हॉटल’ खुलेआम अवैध कब्जे का उदाहरण है।

संदिग्ध आवाजाही, प्रभावशाली नाम और सुरक्षा जोखिम

स्थानीय नागरिकों, मंडी कर्मचारियों और एमसीडी के गुप्त सूत्रों के अनुसार, तब्लीगी जमात से जुड़े लोग यहाँ नियमित रूप से ठहरते रहे हैं। बंगाल, असम, नॉर्थ-ईस्ट, बांग्लादेश और रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय की पृष्ठभूमि से जुड़े संदिग्ध लोगों की आवाजाही देखी गई है। सूत्रों



के अनुसार, अहसान नाम का प्रभावशाली व्यक्ति मंडी के अंदर-बाहर की गतिविधियों का संचालन करता है।

गाजीपुर मंडी रात दो बजे तक सक्रिय रहती है, जहाँ बिना किसी लोगो के सत्यापन के भारी भीड़ और अव्यवस्थित गतिविधियाँ

दिल्ली-एनसीआर की सुरक्षा पर प्रश्न खड़ा करती हैं। अब सवाल मुख्य यह बनता है की जब वहाँ गाजीपुर थाना पुलिस और एमसीडी कर्मचारी बहार से आने वाले सभी ट्रकों जों बकरा और बैस के भरे हुए होते हैं उन ट्रकों से खुलेआम प्रति ट्रक 1000/- रुपये से 1500 रुपये लेकर अवैध वसूली करते दिखते हैं, तब उन सभी ट्रक का स्थाई ट्रोलनुमा नाके पर डाटा बनाया जाता है। रिकॉर्ड रजिस्टर में लिखा जाता है, तो आने जाने वाले कर्मचारियों और मजदूरों का डाटा क्यों नहीं बनाया जाता।

कब होंगी यह सत्यापन प्रक्रिया?

‘500 मीटर पर गाजीपुर थाना, सैकड़ों झुग्गियाँ और पुलिस का रवैया’

गाजीपुर थाना से मात्र 500 मीटर पर सरकारी भूमि पर सौ से अधिक अवैध झुग्गियाँ बनी हैं। आधार, पहचान और सत्यापन को लेकर कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं। इंद्रापुरम क्षेत्र में भी यही हाल है। पुलिस का यह कहना कि “शिकायत होगी तभी कार्रवाई करेंगे”, सीधे तौर पर इमिग्रेशन और विदेशियों संबंधी विधेयक 2025 की भावना पर प्रश्नचिह्न है।

‘इमिग्रेशन और विदेशियों संबंधी विधेयक 2025 बनाम ज़मीनी हकीकत’

कानून लागू होने के बावजूद गाजीपुर मंडी और इंद्रापुरम में सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी-रोहिंग्या झुग्गियाँ मौजूद हैं। डिटेंशन सेंटर की बातें केवल कागज़ों तक सीमित दिखाई देती हैं।

‘फर्जी पहचान, श्रम, भीख और संगठित नेटवर्क’

पाँचों मस्जिदों में संदिग्ध विदेशी नियमित नमाज अदा करते हैं। फर्जी पहचान पत्रों का नेटवर्क सक्रिय है। गाजीपुर मंडी अब श्रम, भीख, कूड़ा बीनने लेंड जिहाद और अवैध गतिविधियों का केंद्र बन चुकी है। बांग्लादेशी-रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय अब ट्रांसजेंडर बनकर मेकअप कर भीख मांगना और अप्राकृतिक कृत्य जगह-जगह देखने को मिलेंगे, जिसमें सस्ती मजदूरी कृ नेटवर्क मयूर विहार, नोएडा, इंद्रापुरम, वैशाली, कौशांबी, आज़ादपुर मंडी और साहिबाबाद सब्जी मंडी तक फैला है।

‘योगी सरकार के निर्देश और प्रशासनिक निष्क्रियता’

निर्देशों के बावजूद न सत्यापन, न कार्रवाई। प्रशासनिक भूमिका पर गंभीर सवाल।

प्रशासन, खुफिया एजेंसियाँ और जवाबदेही

पुलिस जांच से बचती रही। खुफिया एजेंसियाँ निष्क्रिय। यह धर्म नहीं, कानून, सरकारी जमीन और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है।

मीडिया रिपोर्टों में पहले भी सीमांचल, पश्चिम बंगाल के विहार बॉर्डर

के किशन गंज से मजदूरों को मात्र 10 रुपए में भारतीय बना दिया जाता है, और जिसके तार दिल्ली-एनसीआर तक फैले हैं। फर्जी आधार कार्ड नेटवर्क की ओर इशारा भी किया जा चुका है। उदाहरणरूप एस आई आर के उपरांत पच्छिम बंगाल में सैकड़ों फर्जी पहचान पत्रों के प्रमाण नालों में बिखरे पाए जाते हैं।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैध प्रवासियों की पहचान, सत्यापन और डिटेंशन सेंटर भेजने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद गाजियाबाद-दिल्ली बॉर्डर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में न तो कोई व्यापक सत्यापन अभियान दिखता है और न ही ठोस कार्रवाई, जिससे प्रशासनिक भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

‘दिल्ली एनसीआर रीजन एमसीडी के शीर्ष अधिकारियों को सूचना और अगली कार्रवाई’

दिल्ली सी. एम. रेखा गुप्ता, दिल्ली एमसीडी कमिशनर अश्विनी कुमार जिनकी नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई है, पीए मंगल सिंह, विजिलेंस डायरेक्टर, अनिल कुमार यादव, चीफ विजिलेंस, नीवा जैन और गाजीपुर मंडी क्षेत्र के एमसीडी डिप्टी कमिशनर बादल कुमार एवं गाजियाबाद महापौर श्रीमति सुनीता दयाल कों वीडियो-फोटो, बाईट सहित मौखिक और ईमेल द्वारा आधिकारिक शिकायत दी जा रही है।

सवाल आज भी जस के तस कृ

सरकारी जमीन, अधूरा ध्वस्तीकरण, झुग्गियाँ, सत्यापन और जिम्मेदारी किसकी?

‘जनहित की माँग’

संयुक्त जांच, डोर-टू-डोर सत्यापन और निष्पक्ष कार्रवाई।

अब देखना है कृ प्रशासन जागेगा या चुप्पी किसी बड़े खतरे की भूमिका बनेगी।

सवाल आज भी जस के तस हैं कृ

☐ सरकारी जमीन पर ये ढाँचे कैसे खड़े हुए?

☐ आधा ध्वस्तीकरण हुआ, पूरा क्यों नहीं?

☐ मंडी परिसर धार्मिक गतिविधियों का अड्डा कैसे बना?

☐ सैकड़ों झुग्गियाँ किसकी अनुमति से बसीं?

☐ पूर्ण सत्यापन और कार्रवाई की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

जनहित में स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की माँग है कि जामिया गाजीपुर डेरीफॉर्म दिल्ली-96 के नाम से बने सभी अवैध ढाँचों की एमसीडी, पुलिस, डीडीए और खुफिया एजेंसियों द्वारा संयुक्त जांच हो, पूरे क्षेत्र का डोर-टू-डोर सत्यापन कराया जाए और अवैध कब्जों पर तत्काल निष्पक्ष कार्रवाई हो।

अब देखना यह है कि दिल्ली-गाजियाबाद-नोएडा प्रशासन इस खुली चुनौती पर कब जागता है कृ या फिर यह चुप्पी किसी बड़े खतरे की भूमिका बनती रहेगी।

रविंद्र आर्य

वरिष्ठ खोजी पत्रकार एवं लेखक



साप्ताहिक

सबका जम्मू कश्मीर
संपादकीय

विकास बनाम व्यवस्था



संपादक - राज कुमार

आज भारत के शहर एक ऐसा विरोधाभास दिखाते हैं जिसे अब विकास के एक अस्थायी दौर के रूप में नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। फ्लाईओवर चमकते हैं, मेट्रो लाइनें आसमान तक फैली हुई हैं, और टर्मिनल ग्लोबल शोकेस जैसे दिखते हैं। फिर भी, ज़मीनी स्तर पर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहरीली हवा, टूटी सड़कें, ओवरफ्लो होते नाले और नागरिक अव्यवस्था का चुपचाप सामान्य होना आम बात हो गई है। समस्या यह नहीं है कि भारतीय शहरों में पैसे या महत्वाकांक्षा की कमी है। समस्या यह है कि वे संरचनात्मक रूप से खुद पर शासन करने में असमर्थ हैं। शहरी भारत का विस्तार उस गति से हुआ है जिसकी संविधान ने कभी कल्पना नहीं की थी। कस्बे मेगासिटी में बदल गए हैं, और गाँव घने शहरी गलियारों में, बिना राजनीतिक सत्ता में इसी तरह के विकास के। योजना, स्टाफिंग, बजट और यहाँ तक कि छोटे-मोटे ऑपरेशनल फैसलों पर भी शक्ति राज्य की राजधानियों में केंद्रित है। शहर सरकारें मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर लागू करने वालों के रूप में, न कि फैसला लेने वालों के रूप में। इसका नतीजा यह है कि ज़िम्मेदारी और अधिकार के बीच हमेशा एक बेमेल रहता है शहरों को विफलता के लिए दोषी ठहराया जाता है लेकिन सफल होने के लिए ज़रूरी साधन नहीं दिए जाते। यह असंतुलन बताता है कि क्यों हेडलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बुनियादी चीज़ों के ढहने के साथ-साथ मौजूद हैं। कचरा प्रबंधन इसलिए फेल नहीं होता क्योंकि टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसलिए कि नगर निकायों के पास ज़मीन, कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग-टर्म फाइनेंसिंग पर कंट्रोल नहीं है। सड़कें इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि यूटिलिटी कंपनियाँ बिना किसी तालमेल के या सार्वजनिक खर्च की परवाह किए बिना उन्हें खोद देती हैं। बाढ़ बार-बार आती है क्योंकि ड्रेनेज प्लानिंग अलग-अलग एजेंसियों में बंटी हुई है जो अलग-अलग राजनीतिक आकाओं को जवाब देती हैं। कोई भी एक ऑफिस सच में जवाबदेह नहीं है, और इसलिए किसी को भी सिस्टम को शुरू से आखिर तक ठीक करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। भारत की शहरी चुनौती को अक्सर क्षमता की समस्या के रूप में देखा जाता है। असल में, यह शक्ति की समस्या है। मेयर कमज़ोर हैं, परिषदों के पास फंड की कमी है, और शहर प्रशासन में ऐसे अधिकारी हैं जिनके प्रोत्साहन शहरी नतीजों के बजाय राज्य-स्तरीय करियर पथों से तय होते हैं। नेतृत्व कभी-कभी होता है, जो टिकाऊ संस्थानों के बजाय व्यक्तिगत नौकरशाहों पर निर्भर करता है। जब वे व्यक्ति चले जाते हैं, तो सुधार भी उनके साथ चला जाता है। विश्वसनीय डेटा की कमी ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। शहरी आबादी आधिकारिक अनुमानों से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन नीति अभी भी पुराने आंकड़ों पर निर्भर है। सटीक जनसंख्या, आवास या रोज़गार डेटा के बिना योजना बनाना विफलता की गारंटी है, चाहे योजना कितनी भी अच्छी नीयत से बनाई गई हो। शहरों से इक्कीसवीं सदी के दबावों को बीसवीं सदी की मान्यताओं के साथ मैनेज करने के लिए कहा जा रहा है। इसका एक लोकतांत्रिक नुकसान भी है। जब नागरिक रोज़ाना नागरिक व्यवस्था में गड़बड़ी का अनुभव करते हैं और जवाबदेह ठहराने के लिए कोई स्पष्ट अथॉरिटी नहीं होती, तो अलगाव शुरू हो जाता है। गुस्सा कभी-कभी सामने आता है, बाढ़, प्रदूषण बढ़ने या इंफ्रास्ट्रक्चर ढहने के बाद, लेकिन शायद ही कभी संरचनात्मक सुधार के लिए लगातार राजनीतिक दबाव में बदल पाता है। शहरी समस्याओं को राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय सामान्य मान लिया जाता है; यह एक ऐसी स्थिति है जिसका फायदा सिविक नौकरशाही उठाती है। भारत के शहर सिर्फ ऊपरी सुधारों या इक्का-दुक्का सफल कहानियों से रहने लायक नहीं बनेंगे। ज़रूरत है एक बड़े बदलाव की सत्ता का असली विकेंद्रीकरण, भरोसेमंद म्युनिसिपल फाइनेंस, मजबूत मेयर, प्रोफेशनल सिटी कैडर, और नतीजों से जुड़ी पारदर्शी जवाबदेही। विकास ने भारत को असल में पहले ही शहरी बना दिया है। अब शासन को भी सिद्धांत रूप में इसके साथ तालमेल बिठाना होगा। इस सुधार के बिना, भारत के शहर कागज़ पर तो अमीर होते रहेंगे, लेकिन रहने के लिए और खराब जगह बनते जाएंगे।

अरावली पर्वतश्रृंखला पर जारी सियासत के बीच सजग हुई सरकार से जगी उम्मीदें

केंद्र सरकार ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को अरावली क्षेत्र में सतत खनन (नेजंपदइसम डपदपदह) के लिए वैज्ञानिक योजना बनाने का निर्देश दिया है। लिहाजा, यह वैज्ञानिक योजना ही अब देखेगी कि खनन का प्रकृति पर कितना बुरा असर पड़ रहा है और अरावली क्षेत्र कितना भार सह सकता है।

नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर के लिए प्राकृतिक वरदान समझी जाने वाली अरावली पर्वतश्रृंखला पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दृष्टिगत और प्रस्तावित अरावली सत्याग्रह के बीच केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस पर्वतमाला क्षेत्र में अब किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे (माइनिंग लीज) जारी न किए जाएं। इससे साफ है कि अरावली पर्वतश्रृंखला पर जारी सियासत के दृष्टिगत केंद्र सरकार अब सजग हो चुकी है और जनहित के मद्देनजर आवश्यक दिशानिर्देश जारी किया है। इससे अरावली पर्वतश्रृंखला में जैव विविधता के संरक्षण की उम्मीद भी बढ़ी है। यदि वाकई ऐसा होता है तो देश की राजधानी नई दिल्ली के लिए यह शुभ कदम होगा। यहां के जल संरक्षण, वायु संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण आदि की दिशा में इसके सकारात्मक प्रभाव जल्द दिखेंगे।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गत बुधवार को इस बारे में एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया हुआ है कि यह प्रतिबंध गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली पूरी अरावली श्रृंखला पर समान रूप से लागू होगा। मंत्रालय के मुताबिक, यह फैसला अरावली को पर्वतमाला के रूप में सुरक्षित रखने और इसके आसपास चल रहे अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के मकसद से लिया गया है। लगे हाथ सरकार ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (पब्लिस) को यह भी निर्देश दिया है कि वह पूरे अरावली रीजन में ऐसे जोन की पहचान करे, जहां खनन पर पूरी तरह से बैन लगाया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा था कि आसपास की जमीन से कम से कम 100 मीटर ऊंचे हिस्से को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इसप्रकार इस नए मानक से कई ऐसी पहाड़ियों पर खनन का डर पैदा हुआ, जो 100 मीटर से छोटी और झाड़ियों से ढकी हुई हैं। यही वजह है कि पर्यावरण प्रेमियों ने इसे मुद्दा बना दिया और राजनीतिक दलों के मुखर होने से विरोध तेज हुआ। हालांकि अरावली सत्याग्रह की हवा निकालने के लिये केंद्र सरकार ने समय रहते ही समुचित कदम उठा लिए। साथ ही इसके इर्द-गिर्द पुनः हरियाली वापस लाने के उपाय करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

वहीं, केंद्र सरकार ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को अरावली क्षेत्र में सतत खनन (नेजंपदइसम डपदपदह) के लिए वैज्ञानिक योजना बनाने का निर्देश दिया है। लिहाजा, यह वैज्ञानिक योजना ही अब देखेगी कि खनन का प्रकृति पर कितना बुरा असर पड़ रहा है और अरावली क्षेत्र कितना भार सह सकता है। जहां खनन हो चुका है, उन क्षेत्रों को फिर



से सुधारने और वहां पर हरियाली वापस लाने के उपाय किए जाएंगे। यह दूरदर्शिता भरा कदम है जो सराहनीय है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि जो खदानें पहले से संचालित हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का राज्य सख्ती से पालन कराए जाएं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौजूदा खनन गतिविधियों को भी कड़े नियमों और अतिरिक्त प्रतिबंधों के तहत कंट्रोल किया जाएगा।

बताते चलें कि अरावली अस्तित्व संकट मुख्य रूप से अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षरण से जुड़ा है, जो 1990 के दशक में शुरू हुआ। इस दौरान राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में खनन गतिविधियों से पहाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन की शिकायतें 1990 के दशक से बढ़ने लगीं, जब संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे खनिजों के दोहन से पर्यावरण, जल संकट और वायु प्रदूषण उभरा।

अलबत्ता 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार हस्तक्षेप कर कुछ क्षेत्रों में खनन रोक दिया।

वहीं 2002 में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने हरियाणा और राजस्थान में पूर्ण खनन प्रतिबंध लगाया। तत्पश्चात 2003 का विवादास्पद मर्फी फॉर्मूला लागू हुआ, जिसने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को खनन योग्य घोषित किया।

पुनः बढ़ते विरोध के मद्देनजर 2009 में हरियाणा के कई जिलों में स्थायी प्रतिबंध लगा। जहां तक इसे मुद्दे पर हालिया विकास की बात है तो नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा (100 मीटर ऊंचाई) मंजूर की, जिससे खनन का खतरा फिर बढ़ गया है। यह थार रेगिस्तान के विस्तार और दिल्ली-एनसीआर के पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है।

अरावली में अवैध खनन मुख्य रूप से 1990 के दशक से तेजी से बढ़ा, जब संगमरमर, ग्रेनाइट और चूना पत्थर जैसे

खनिजों की मांग बढ़ने लगी।

यह राजस्थान, हरियाणा और गुजरात की सीमाओं पर जंगलों के बीच गुप्त सड़कों और रात के अंधेरे में विस्फोटों के जरिए फैला। इसके बढ़तेरी के कारण खनन माफियाओं ने स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से जंगल काटे, डंपरों के लिए रास्ते बनाए और सप्ताहांतों पर बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग की।

आंकड़े बताते हैं कि 1975 से 2019 तक अरावली की 8 पहाड़ियां गायब हो चुकी थीं, जिसमें अवैध खनन की मुख्य भूमिका रही। 2018 तक राजस्थान में 25 अरावली प्रभावित क्षेत्र नष्ट हो चुका। नूह, चित्तौड़ा जैसे इलाकों से 8 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक सामग्री गायब। आलम यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधों के बावजूद सरिस्का जैसे संरक्षित क्षेत्रों में जारी। वहीं, हालिया स्थिति यह है कि 2024-2025 में हरियाणा-राजस्थान सीमा पर 30 से अधिक गांवों में खनन माफिया सक्रिय, जिससे धूल भरी आधियां और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा। इससे सतर्क हुए एनजीटी ने कई बार जांच के आदेश दिए।

देखा जाए तो अरावली संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं, जहां अवैध खनन ने पहाड़ियों को नष्ट किया। राजस्थान के जिले अलवर, जयपुर, सीकर और उदयपुर जैसे जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए, जहां सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास खनन माफिया सक्रिय रहे।

यहां 1990 से 25 क्षेत्र नष्ट हो चुका। वहीं, हरियाणा के जिले नूह (मेवात), गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में 30 से अधिक गांव खनन से तबाह, धूल भरी आधियां दिल्ली-एनसीआर तक पहुंचीं। वहीं गुजरात के जिले साबरकांठा और बनासकांठा जिलों में चूना पत्थर खनन से अरावली का बड़ा हिस्सा गायब। कुल मिलाकर, इन जिलों में 1975-2019 तक 8 पहाड़ियां समाप्त हो चुकीं।

— कमलेश पांडेय

वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

बीजेपी नेताओं ने महात्मा बाबा बूटा राम जी की 56वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी

सबका जम्मू कश्मीर

मीरां साहिब (जम्मू) : महात्मा बाबा बूटा राम जी की 56वीं पुण्यतिथि मीरां साहिब, जम्मू में महाशा सुधार सभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई।

जम्मू-कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा, बीजेपी राष्ट्रीय सचिव और विधायक डॉ. नरेंद्र सिंह, विधायक डॉ. देवेंद्र कुमार मन्याल और प्रो. धरु राम भगत, पूर्व एमएलसी विमोघ गुप्ता, जिला प्रभारी अयोध्या गुप्ता, डीडीसी सदस्य विद्या मोहन और बलबीर, साथ ही कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर महात्मा बाबा बूटा राम जी को श्रद्धांजलि दी।

महाशा सुधार सभा के नेताओं और सदस्यों, जिनमें कार्यकारी अध्यक्ष बिशन दास, सभापति एडवोकेट बोध राज राव, कार्यकारी सभापति कर्नल सोम नाथ डोगरा (सेवानिवृत्त), कैप्टन सोम दत्त (सेवानिवृत्त), हल्का अध्यक्ष सुरेंद्र कलोत्रा, कैशियर जसबीर कुमार, पंडित श्याम लाल और अन्य शामिल थे, ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। महात्मा बाबा बूटा राम जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई, और जरूरतमंदों के बीच विभिन्न आवश्यक वस्तुएं वितरित की गईं, जो संत के जीवन भर के सेवा और करुणा के संदेश को दर्शाती हैं।

सभा को संबोधित करते हुए सत शर्मा ने कहा कि महात्मा बाबा बूटा राम जी एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण और दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि बाबा



जी का सादा जीवन, निस्वार्थ सेवा और गहरी आध्यात्मिक ज्ञान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। ऐसे संत लोगों को धार्मिकता, सद्भाव और मानवता की सेवा की ओर मार्गदर्शन करके समाज के नैतिक और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करते हैं। सत शर्मा ने कहा कि बाबा जी को याद करना सामाजिक एकता और गरीबों के कल्याण के लिए काम करने की याद दिलाता है। डॉ. नरेंद्र सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि महात्मा बाबा बूटा राम जी का बहुत कम उम्र से ही फकीरी ध्वजा और गहरा झुकाव था। उन्होंने कहा कि बाबा जी ने बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और लोगों के लिए, खासकर आरएस पुरा क्षेत्र में, जहां उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया, विश्वास और आशा का प्रतीक बन गए। डॉ. देविंदर कुमार मन्याल ने कहा कि महात्मा बाबा बूटा राम जी का जीवन आध्यात्मिक अनुभवों से भरा था, जिसने लोगों का दिव्य शक्ति और सच्चाई में विश्वास मजबूत किया। उन्होंने इस बात पर

जोर दिया कि बाबा जी की दया, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा की शिक्षाएं आज की भौतिकवादी दुनिया में बहुत प्रासंगिक हैं।

प्रोफेसर धरु राम भगत ने कहा कि महात्मा बाबा बूटा राम जी, जिनका 1969 में स्वर्गवास हो गया था, उनके पास महान दैवीय और अलौकिक शक्तियां थीं और सभी समुदायों में उनका सम्मान किया जाता था। उन्होंने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व सामाजिक सद्भाव, भाईचारा और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

महाशा सुधार सभा के प्रतिनिधियों ने आभार व्यक्त किया और कहा कि सभा बाबा जी की आध्यात्मिक, सामाजिक और मानवीय विरासत को संरक्षित करने और उसका प्रचार करने के लिए लगातार काम कर रही है। सभा के प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे वार्षिक आयोजन युवा पीढ़ी को महात्मा बाबा बूटा राम जी द्वारा दिखाए गए निस्वार्थ सेवा, सामाजिक सद्भाव और दया के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।

उच्च न्यायालय गंभीर अपराधों के मामलों में निचली अदालतों को साक्ष्य बंद करने से बचना चाहिए।

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों से हत्या जैसे जघन्य अपराधों में साक्ष्य को छिपाने से परहेज करने पर जोर दिया है, क्योंकि इससे न्याय में विफलता हो सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने से बचकर मुकदमे को लंबा खींचने के लिए इसका दुरुपयोग न करे। न्यायमूर्ति संजय धर ने कहा कि यद्यपि निचली अदालत के पास अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को बंद करके मुकदमे को समाप्त करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हत्या जैसे जघन्य अपराधों में, अदालतें आमतौर पर यह चरम कदम नहीं उठाती हैं, विशेषकर तब जब जांच के लिए पेश किए जाने वाले गवाह विशेषज्ञ गवाह और जांच अधिकारी हों।

न्यायमूर्ति धर ने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में साक्ष्यों को बंद करने से परहेज करती हैं, अन्यथा इससे न्याय में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

ये टिप्पणियां अदालत ने फहद



मकसूद खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं, जिस पर हत्या का आरोप है और जो पिछले 13 वर्षों से जेल में है क्योंकि मामले की सुनवाई साक्ष्य चरण में है। खान ने केवल अपनी लंबी कैद और शीघ्र सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर जमानत मांगी है। "अदालत ने पाया है कि याचिकाकर्ता ने 13 वर्षों से अधिक समय तक कारावास में रहने और अभियोजन पक्ष और पुलिस विभाग के आचरण के कारण निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की संभावना न के बराबर होने के कारण जमानत देने का आधार बनाया है,"

अदालत ने कहा। "उसने धारा 483 के तहत जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है। यह मामला पुलिस स्टेशन सदर, श्रीनगर में धारा 302, 307, 326, 324, 506, 201, 120-बी, 34 आरपीसी के तहत अपराधों के लिए एफआईआर संख्या 135/2012 से संबंधित है, जिसका मुकदमा श्रीनगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित है।"

अदालत ने आगे कहा कि निचली अदालत के बार-बार निर्देश देने के बावजूद अभियोजन पक्ष गवाहों की उपस्थिति दर्ज कराने में असमर्थ रहा है। जिन

गवाहों के बयान अभी दर्ज किए जाने बाकी हैं, उनमें विशेषज्ञ और पुलिस अधिकारी शामिल हैं।

"इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां कुछ दीवानी गवाह, जिन्हें आरोपी ने अपने पक्ष में कर लिया हो, अभियोजन पक्ष के समर्थन में गवाही देने से बच रहे हों, बल्कि यह ऐसा मामला है जहां सरक. 191 गवाह भी मामले की शीघ्र सुनवाई में अभियोजन पक्ष की मदद करने से बच रहे हैं," फैसले में कहा गया है।

निचली अदालत के रिकॉर्ड को देखने से स्पष्ट है कि 33 गवाहों में से, अब तक निचली अदालत ने 13 साल से अधिक समय तक चले लंबे मुकदमे के दौरान 29 अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ की है और चार अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ अभी बाकी है।

न्यायमूर्ति धर ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने मुकदमे को पूरा करने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अथक प्रयास किए हैं, जिसके लिए निचली अदालत प्रशंसा की पात्र है।

सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद, कांग्रेस ने एमजीएनआरईजीए को बचाने के लिए अभियान की घोषणा की

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : कांग्रेस ने शनिवार को एमजीएनआरईजीए को निरस्त करने के खिलाफ 5 जनवरी से राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की, जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यूपीए काल के इस कानून को खकेले ही नष्ट करने का आरोप लगाया और दावा किया कि यह लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में योजना की घोषणा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने राहुल गांधी के साथ कहा कि उनका आंदोलन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन जैसा होगा, जिसके चलते अंततः नरेंद्र मोदी सरकार को उन्हें वापस लेना पड़ा था।

बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की लगभग तीन घंटे चली बैठक के बाद, जो कि पहली बैठक थी, खर्गे ने कहा कि पार्टी 5 जनवरी से एमजीएनआरईजीए बचाओ अभियान का नेतृत्व करेगी और जल्द ही एक विस्तृत योजना की घोषणा की जाएगी जिसके तहत देशभर में रैलियां आयोजित की जाएंगी।

सीडब्ल्यूसी बैठक से पहले हलचल मचाते हुए, दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और भाजपा की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा की और नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए बताया कि कैसे एक जमीनी कार्यकर्ता उनके नेताओं के चरणों में बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गया। बाद में उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने और उसकी राज्य इकाइयों के विकेंद्रीकरण का मुद्दा उठाया।

समिति समिति की बैठक के दौरान, कांग्रेस नेताओं ने एमजीएनआरईजीए की हर कीमत पर रक्षा करने और देश के श्रमिकों के सम्मान, रोजगार और उचित एवं समय पर मुआवजे के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष करने की शपथ ली। विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 20 साल पुराने एमजीएनआरईजीए की जगह लेने वाला वीबी-जी आरएएमजी विधेयक पारित किया गया।

खर्गे ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) केवल एक योजना नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त श्रम का अधिकार है।

रात का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिर गया

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : कश्मीर में रात का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिर गया क्योंकि साफ आसमान के कारण अधिकांश स्थानों पर पारा गिर गया।

मौसम अधिकारियों ने आज कहा कि घाटी नव वर्ष की पूर्व संध्या के आसपास बारिश और बर्फबारी के एक और दौर के लिए तैयार हो रही है। श्रीनगर में शुक्रवार रात न्यूनतम तापमान -2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछली रात के 0.2 डिग्री सेल्सियस से लगभग तीन डिग्री कम है।

मध्य कश्मीर का पर्यटन स्थल सोनमर्ग जम्मू और कश्मीर में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान -5.8 डिग्री सेल्सियस था, जो एक दिन पहले के -4.7 डिग्री सेल्सियस से कम है।

कि दक्षिण कश्मीर का पहलगाम पर्यटन स्थल, जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए एक बेस कैंप के रूप में भी कार्य करता है, -4.8 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरा सबसे ठंडा स्थान रहा। उन्होंने बताया कि उत्तरी कश्मीर के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अन्य स्थानों में, काजीगुंड में न्यूनतम तापमान -2.8 डिग्री सेल्सियस, कोकरनाग में -0.9 डिग्री सेल्सियस और कुपवारा में -3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

भारतीय मौसम विभाग ने कश्मीर में 29 दिसंबर तक सामान्यतः शुष्क मौसम और नव वर्ष की पूर्व संध्या के आसपास बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है।

मौसम विभाग ने बताया कि 30 दिसंबर को छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कई स्थानों पर ऐसा हो सकता है। विभाग ने कहा कि उत्तरी और मध्य कश्मीर के कुछ मध्य और ऊंचे इलाकों में मध्यम बर्फबारी की संभावना है। 2

जनवरी को कुछ अलग-थलग ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उधमपुर में ड्रग तस्करी की 1.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

सबका जम्मू कश्मीर

यहां जारी एक बयान में पुलिस ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, उधमपुर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68(एफ) के तहत लगभग 1.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई रेहंबल पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 21 और 22 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 117/2025 के संबंध में की गई है। जब्त की गई संपत्तियां वाहिद मकबूल मीर, पुत्र मोहम्मद मकबूल मीर की हैं, जो बांदिपोरा जिले के सुंबल के शिलवेट क्षेत्र का निवासी है। जब्त की गई संपत्तियों में बांद. पोरा जिले के सुंबल के शिलवेट में सर्वे संख्या 344 (आबादी देह) के अंतर्गत आने वाली आठ मरला भूमि पर निर्मित एक दो मंजिला



आवासीय मकान भी शामिल है। पंजीकरण संख्या जेके19-1061 और जेके01एन-7343 वाले दो टिपर वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान विस्तृत वित्तीय जांच और बैकवर्ड लिंकेज विश्लेषण से पता चला कि आरोपियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से संपत्तियां खरीदी थीं।

बयान में कहा गया है, छन निष्कर्षों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने आज कुर्की आदेश पारित किया है और एनडीपीएस अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। इस कार्रवाई के साथ, उधमपुर पुलिस द्वारा चालू वर्ष में एनडीपीएस की संपत्ति कुर्क करने की कुल राशि 18.85 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो मादक

पदार्थों के तस्करी के खिलाफ पुलिस की निरंतर कार्रवाई को दर्शाती है। पुलिस ने आगे बताया कि

जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल केंद्र शासित प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों, ड्रग पेडलर्स और हवाला लेनदेन तथा अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहे हैं।

इन कार्रवाइयों में आरोपियों को सख्त कानूनों के तहत हिरासत में लेना और इन अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन से अर्जित संपत्तियों को जब्त करना शामिल है।

पुलिस का मानना ​​छह है कि मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध बिक्री और हवाला रैकेट से प्राप्त धन का इस्तेमाल अंततः जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

जम्मू-कश्मीर घ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : भाजपा के अलावा कई हिंदू संगठनों ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर के किश्तवार जिले में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित हमले, आगजनी, लूटपाट और हत्याओं की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया।

सनातन धर्म सभा द्वारा बुलाए गए बंद के कारण कई दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सनातन

धर्म सभा के अध्यक्ष महंत राम शरण दास आचार्य के नेतृत्व में कई हिंदू संगठनों ने कुलीद चौक पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों, जिनमें मंदिरों पर कथित हमले और महिलाओं के खिलाफ हिंसा शामिल हैं, के विरोध में प्रदर्शन किया।

धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त की।

जम्मू और कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता भी धरने में शामिल हुए। विपक्ष के नेता सुनील

शर्मा ने यहां पत्रकारों से कहा, "आज किश्तवार में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सनातन धर्म सभा के आह्वान पर किश्तवार में बंद रहा।"

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अत्याचार झेल रहे अपने समुदाय के सदस्यों के साथ हिंदू मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा, "हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। एक कारखाने में काम करने वाले दीपू की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।" एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि सनातन धर्म सभा के बैनर तले लोग भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह एवं विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हिंदुओं को बचाने और उनकी संपत्ति एवं धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की जाएगी। एक अन्य नेता, रॉकी गोस्वामी ने कहा कि वे बांग्लादेश में दीपू दास की क्रूर हत्या से अवगत हैं। उन्होंने कहा, "इन घटनाओं के विरोध में सनातन धर्म सभा ने किश्तवार में बंद का आह्वान किया है। इस आह्वान के तहत बांग्लादेश के पुतले जलाए जा रहे हैं। लोगों में स्पष्ट आक्रोश है और सनातन समुदाय के सदस्य बड़ी संख्या में एकजुट हुए हैं।"

तीन पूर्व प्रवासी श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया, उन पर जन जागरूकता अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : पुलिस ने आज दक्षिण कश्मीर के शोपियन जिले में तीन ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया।

एक पुलिस प्रवक्ता ने यहां बताया कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस के निरंतर प्रयासों के तहत तीनों को गिरफ्तार किया गया और उन पर जन जागरूकता अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार किए गए अवैध सशस्त्र बलों (ओजीडब्ल्यू) की पहचान सेडो शोपियां निवासी औवैस अहमद लोन, शाहलातू शोपियां निवासी मशूक अहमद शाह और चेक चोलैंड शोपियां निवासी सुब्जार अहमद गनी के रूप में हुई है। प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में बार-बार शामिल पाए गए। उन्होंने आगे कहा, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170/126 के तहत उनके खिलाफ निवारक कार्रवाई और कार्यवाही शुरू किए जाने के बावजूद, वे गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहे।

हादी के बाद, बांग्लादेश के एक और छात्र नेता को सिर में गोली मार दी गई

सबका जम्मू कश्मीर

ढाका : अज्ञात बंदूकधारियों ने सोमवार को बांग्लादेश के हिंसक छात्र-नेतृत्व वाले 2004 के विद्रोह के दूसरे नेता मोतालेब शिकदर को सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। यह हमला दक्षिण-पश्चिमी शहर खुलना में प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के कुछ दिनों बाद हुआ।

एनसीपी (राष्ट्रीय नागरिक पार्टी) के संयुक्त प्रधान समन्वयक महमूदा मितु ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, एनसीपी के खुलना डिवीजन के प्रमुख और पार्टी के कार्यकर्ता मोर्चे के केंद्रीय समन्वयक, मोतलेब शिकदर को कुछ मिनट पहले गोली मार दी गई।

डॉक्टर मीतु ने बताया कि शिकदर को गंभीर हालत में खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया।

कलेर कंथा अखबार ने अस्पताल के सूत्रों के हवाले से बताया कि शिकदर के सिर के बाएं हिस्से में गोली लगी थी और जब उसे अस्पताल लाया गया तो वह बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जहां डॉक्टरों ने उसका आपातक.ालीन इलाज शुरू किया।

यह हमला हादी की हत्या के कुछ दिनों बाद हुआ है। हादी पिछले साल छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के एक प्रमुख नेता थे, जिनके कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर



दिया गया था। हादी को 12 दिसंबर को मध्य ढाका के बिजोयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी।

32 वर्षीय इंकलाब मंच के प्रवक्ता का गुरुवार को सिंगापुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। हादी 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में उम्मीदवार थे।

मोहम्मद युनुस की अंतरिम सरकार ने शनिवार को हादी की मौत पर राष्ट्रव्यापी शोक का आयोजन किया और कहा कि उनके हत्यारों को पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि हमले और उसके बाद हुई मौत को लेकर ढाका और अन्य प्रमुख शहरों में हिंसा फिर से भड़क उठी।

पुलिस ने फैसल करीम मसूद के माता-पिता,

पत्नी और मुख्य संदिग्ध की एक महिला मित्र को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में अनिश्चित हैं। सोमवार को खुलना शहर के माजिद सरानी इलाके में शिकदर पर हुए गुप्त हमले के बाद, पुलिस ने कहा कि वे अभी तक हमले के अपराधियों या मकसद के बारे में अनजान हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए प्त्तकाल तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि, स्थानीय पुलिस स्टेशन प्रमुख अनिमेष मंडल ने पत्रकारों को बताया कि खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (केएमसीएच) के अधिकारियों ने शिकदर को उसकी चोट की स्थिति का सटीक पता लगाने के लिए अपने सिटी इमेजिंग सेंटर में स्थानांतरित कर दिया है।

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर के वन क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान का दायरा बढ़ाया गया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के वन क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान का दायरा बढ़ा दिया।

अधिकारियों

ने बताया कि घेराबंदी और तलाशी अभियान, जो दूसरे दिन में प्रवेश कर गया, रविवार को मजालता के जंगलों में तब शुरू किया गया जब दो आतंकवादियों के एक घर से खाना लेकर पास के जंगल में भाग जाने की खबर मिली। उन्होंने

बताया कि।

खोजी कुत्तों और हवाई निगरानी की मदद से चलाए जा रहे घेराबंदी और तलाशी अभियान का दायरा सोमवार सुबह जंगल क्षेत्र में लगभग दस किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया ताकि मजालता क्षेत्र में छिपे दो आतंकवादियों को पकड़ा जा

सके।

पिछले कुछ दिनों में तीसरी बार जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों को देखे जाने के बाद यह विस्तार आवश्यक हो गया था। रविवार रात को भी दोनों की गतिविधि की सूचना मिली थी।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और

अर्धसैनिक बलों द्वारा संयुक्त तलाशी अभियान मजालता क्षेत्र के चोरे मोटू और उसके आसपास के वन गांवों में जारी है।

जो उस जगह से लगभग पांच किलोमीटर पश्चिम में है जहां पहले मुक़भेड़ हुई थी जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था।

बीजेपी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन और विरासत पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणादायक जीवन यात्रा, विचारा और योगदान को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन बीजेपी मुख्यालय, त्रिकुटा नगर, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी अटल स्मृति वर्ष कार्यक्रमों के तहत किया गया।

जम्मू-कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा, बीजेपी जम्मू-कश्मीर महासचिव (संगठन) अशोक कौल और लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बाद में, वरिष्ठ नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की।

प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए सत शर्मा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक संस्था थे, जिनका जीवन पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति और राष्ट्र निर्माण में अटल जी का योगदान अद्वितीय है, क्योंकि उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी परिपक्वता, संतुलन और साहस के साथ देश का नेतृत्व किया।



सत शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि अटल जी ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया, राष्ट्रीय हित को दृढ़ता से बनाए रखा और साथ ही राजनीतिक चर्चा में गरिमा बनाए रखी।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर सम्मानित भारत का निर्माण करके अटल जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।

अशोक कौल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी विचारधारा में निहित, फिर भी संवाद और आम सहमति के लिए खुले सिद्धांतों वाली राजनीति के प्रतीक थे।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अटल स्मृति वर्ष के माध्यम से, बीजेपी अटल जी के आदर्शों को जमीनी स्तर पर, विशेष रूप से युवाओं के बीच ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे राष्ट्रवाद,

सुशासन और नैतिक राजनीति के मूल्यों को समझ सकें।

जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि अटल जी का जीवन दृढ़ राष्ट्रवाद और करुणामय शासन का एक अनूठा मिश्रण था।

उन्होंने कहा कि अटल जी की कविताएं समाज और मानवता के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता को दर्शाती थीं, जबकि उनके शासन ने भारत के आधुनिक बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और रणनीतिक ताकत की नींव रखी।

जम्मू-कश्मीर बीजेपी उपाध्यक्ष भरत भूषण और रेखा महाजन, महासचिव संजीता डोगरा, बलदेव सिंह बिल्लवारिया और गोपाल महाजन, विधायक युद्धवीर सेठी, चौधरी विक्रम रंधावा, और अरविंद गुप्ता, पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा, पूर्व एमएलसी एडवोकेट।

विबोध गुप्ता, अरुण शर्मा, पवन शर्मा, तिलक राज गुप्ता, डॉ. प्रदीप महोत्रा, वेद शर्मा, प्रदुमन सिंह, प्रोफेसर कुलभूषण मोहत्रा, विनय गुप्ता, बलबीर राम रतन, जोरावर सिंह जम्वाल, मुनीश खजूरिया, ब्रह्मज्योत, अरुण प्रभात, नेहा महाजन, अयोध्या गुप्ता, डॉ. मैकसन टिक्कू, नवीन शर्मा, जीत अंगराल और अन्य उपस्थित थे।

45 प्रतिकूल घटनाएं बर्ही; 77 प्रतिकूल घटनाएं और प्रतिकूल घटनाएं स्थानांतरित हुईं, जिन्हें पीडीडी में पीडी दर्ज किया गया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : सरकार ने आज विद्युत विभाग के 39 प्रभारी सहायक अभियंताओं (एई) को प्रभारी सहायक कार्यकारी अभियंताओं (एईई) के पद पर पदोन्नत/स्थापित किया और विद्युत विकास विभाग (पीडीडी) में 77 प्रभारी एईई और प्रभारी एईई का तबा. दला/तैनात किया।

आई/सी एईई (25 डिग्री धारक) के रूप में पदोन्नत किए गए लोग हैं: विशाल शर्मा, विनोद माथुर, सईद अहमद फारुकी, मोहम्मद अशरफ, रिप्पन कुमार, मसूद-उल-शरीफ जरगर, तालिब हुसैन गिलानी, सुनील कुमार, खुशीद अहमद भट, विजय कुमार, प्रेरणा भगत, अमजद परवेज, नवनीत गुप्ता, परशोतम कुमार, केशव चंदर खजूरिया, मोहम्मद खान, पृथ्वीपाल सिंह, मुश्ताक अहमद, हकीम-उद-दीन खान, राकेश कुमार बंगोत्रा, मकबूल हुसैन, पवन कुमार, साजदा बेगम, मोहम्मद रफीक खान और विजय कुमार शर्मा। डिप्लोमा धारक 15 लोगों को प्रभारी सहायक कर्मचारी (एईई) के पद पर पदोन्नत किया गया है: शाह मेहरोज अहमद, गौहर रफीकी, अनुराधा गुप्ता, निशी बाला, रेखा जारू, स्वाइबा जान कादरी, रवि जी कौल, अरविंद शर्मा, रजनी शर्मा, वसीम सज्जाद, रुबी जान, शमाश कालू, रीता गुप्ता, रंजय गुप्ता और मोहम्मद इकबाल वदू।

उपरोक्त नियुक्तियों के परिणामस्वरूप, आज 77 प्रभारी सहायक कर्मचारी (एईई)/एईई का तबा. दला/पोस्टिंग की गई। सैयद फारुक को डिवीजन-ए जेकेपीडीसीएल में; मोहम्मद अशरफ को एसडी तंगधार ईडी कुपवाड़ा केपीडीसीएल में; विशाल शर्मा को एसडी रामकोट ईडी कठुआ जेपीडीसीएल में; रिप्पन कुमार को एसडी-ए एसएलडीसी, जेकेपीटीसीएल जम्मू में; मसूद उल-शरीफ को एसडी-ए ईडी डोडा, जेपीडीसीएल में; विनोद माथुर को एसडी-ए ईडी डोडा जेपीडीसीएल में; तालिब हुसैन को ईडी शोपियां, एसडी शोपियां केपीडीसीएल में तैनात किया गया है। सुनील कुमार को एसडी-रामगढ़ ईडी विजयपुर जेपीडीसीएल; खुशीद अहमद से एसडी-लंगेट, ईडी हंदवाड़ा; विजय

कुमार को एसडी धर्माई ईडी रियासी; प्रेरणा भगत को निरीक्षण मंडल जम्मू; अमजद परवेज को एमडी, जेकेपीडीसी कार्यालय; नवनीत गुप्ता को जहांगीर अहमद के स्थान पर एक्सईएन एसटीडी-ए जेपीडीसीएल में तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया; पुरुषोत्तम कुमार को ईडी-ए, एसडी प्लांट जेपीडीसीएल भेजा गया; केशव चंदर को ईडी-ए, एसडी नहर जेपीडीसीएल; मोहम्मद खान को तकनीकी अधिकारी के रूप में ईडी पुंछ में नियुक्त किया गया; पृथपाल सिंह को योजना मंडल जेपीडीसीएल, जम्मू; मुश्ताक अहमद को एसडी-द्वितीय ईडी बारामूला केपीडीसीएल; हकीम-उद-दीन से एसडी नवाकदल ईडी-ए केपीडीसीएल; राकेश कुमार को कॉर्पोरेट कार्यालय, एमडी जेकेपीटीसीएल; मकबूल हुसैन से एसडी मंदर ईडी पुंछ; पवन कुमार एसडी बिलावर ईडी कठुआ; मोहम्मद रफीक को ईडी-द्वितीय, एसडी हजरीबाग; साजदा बेगम से ईडी-ए, एसडी नगरोटा; विजय कुमार शर्मा से एसडी कोटरका, ईडी राजौरी; शाह मेहरोज से ईडी-ए, एसडी पथरमसिजद; एमडी जेकेपीडीसी के निपटान में गौहर रफीकी; अनुराधा गुप्ता को टीएलएमडी-ए। उधमपुर, एसडी-ए जेकेपीटीसीएल; निशि बल्ला से एसडी स्टोर, टीएलएमडी-ए। जेकेपीटीसीएल; रेखा जारू को डिवीजन-ए। जेकेपीटीसीएल; स्वाइबा जान से साइबर सुरक्षा एलडीसी जेकेपीटीसीएल कश्मीर; रवि जी कौल को टीएलएमडी-ए। जम्मू से एक्सईएन को टीओ बनाया गया; अरविंद शर्मा को ईडी-ए। परेड जेपीडीसीएल में एक्सईएन के रूप में टीओ; रजनी शर्मा को प्लानिंग एसई प्लानिंग सर्कल जेपीडीसीएल जम्मू की ओ/ओ नियुक्त किया गया; वसीम सज्जाद को एसटीएफ बिजनेस केपीडीसीएल में टीओ के रूप में एक्सईएन; रुबी जान से टीएलएमडी-ए। एसडी-ए। अमरगढ़ जेकेपीटीसीएल; शमाश कालू को प्लानिंग सर्कल जेपीडीसीएल; रीता गुप्ता को ओएंडएम सर्कल जम्मू से टीओ से एसई; मोहम्मद इकबाल वाडू को एसडी बनिहाल से ईडी बटोटे जेपीडीसीएल और रंजय गुप्ता को एसडी-ए। सिधरा टीएलएमडी-बी जेकेपीटीसीएल, जम्मू।

सभी 20 डीडीसी को लगभग दो महीने के लिए नई ऊर्जा मिलती है



सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू और कश्मीर में बीस जिला विकास परिषदों (डीडीसी) - प्रत्येक 20 जिलों में एक - को सरकार के विधि विभाग की राय के बाद लगभग दो महीने का नया जीवनदान मिला है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि उनका कार्यकाल 27 दिसंबर, 2025 के बजाय 24 फरवरी, 2026 को समाप्त होगा।

जम्मू और कश्मीर में पहली बार गठित पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों को पूरा करने वाली डीडीसी (विभागीय विकास परिषद) के पांच वर्षीय कार्यकाल की गणना को लेकर पहले एक पेचीदा स्थिति उत्पन्न हो गई थी। डीडीसी सदस्यों ने 28 दिसंबर, 2020 को शपथ ली थी, जबकि परिषदों का औपचारिक गठन 25 फरवरी, 2021 को हुआ था। यह भ्रम कार्यकाल की तारीख को ध्यान में रखने को लेकर था, जिसमें सदस्यों द्वारा शपथ लेने की तारीख या निकायों के गठन की तारीख को शामिल किया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने एक्सेलिसियर को बताया कि

सरकार के विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग, जिसे ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा यह मुद्दा भेजा गया था, ने कहा है कि डीडीसी को उनके गठन की अधिसूचना जारी होने की तारीख, यानी 25 फरवरी, 2021 से विधिवत गठित माना जाएगा।

विधि विभाग ने अपने मत के समर्थन में जम्मू और कश्मीर पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 108C के उप-नियम (2) और उप-नियम (3) का हवाला दिया है। उप-नियम (2) में यह प्रावधान है कि निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के नाम प्राप्त होने पर सरकार अधिसूचना द्वारा संबंधित जिले के नाम से जिला विकास परिषदों का गठन करेगी। सूत्रों के अनुसार, उप-नियम (3) में कहा गया है कि उप-नियम (2) के तहत ऐसी अधिसूचना जारी होने पर जिला विकास परिषद विधिवत गठित मानी जाएगी।

कानूनी राय के अनुसार, जिला विकास परिषदों का पांच वर्षीय कार्यकाल अब अगले वर्ष 24 फरवरी को समाप्त होगा।

सूत्रों ने बताया, यदि शपथ ग्रहण दिवस, यानी 28 दिसंबर, 2020 को जिला विकास परिषदों के पांच वर्षीय कार्यकाल की गणना में शामिल किया जाता, तो परिषदें आज अस्तित्व में नहीं होतीं। उन्होंने आगे कहा कि अब उन्हें लगभग दो महीने का नया जीवन मिला है।

जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 के अनुसार, जिला विकास परिषद का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, सिवाय उन मामलों के जहां पंचायतों के सभी स्तरों के लिए एक साथ आम चुनाव कराए जाते हैं ताकि जिले में सभी स्तरों का कार्यकाल समान हो।

प्रत्येक जिला विकास परिषद में 14 निर्वाचित सदस्य होते हैं। जम्मू और कश्मीर में 20 जिले हैं, इसलिए निर्वाचित जिला विकास परिषद सदस्यों की कुल संख्या 280 है।

हालांकि, केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा जिला विकास परिषदों के चुनाव कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाने के कारण, पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर 24 फरवरी, 2026 से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पंचायतों, नगरपालिकाओं और ब्लॉक विकास परिषदों (बीडीसी) का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है।

जम्मू क्षेत्र में भाजपा छह परिषदों में सत्ता में है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तीन निकायों पर शासन कर रही है। पुंछ डीडीसी की अध्यक्ष एक निर्दलीय हैं।

साप्ताहिक राशिफल



मेप

मेप राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी कभी गम लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको निजी जीवन से लेकर करियर-कारोबार तक में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहने वाली है। इस दौरान व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से खुद को मजबूत पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज-मस्ती करते हुए बीतेगा। घर-परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सप्ताह के मध्य में आपको करियर-कारोबार में कुछ अप्रत्याशित बदलाव को झेलना पड़ सकता है।

इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है। जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता रहेगी।



वृषभ

वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। वृष राशि के जो जातक किसी कार्य विशेष के लिए बीते कुछ समय से लगातार प्रयासरत हैं, उन्हें इस सप्ताह भी उससे जुड़ी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले उनका पूर्वार्ध थोड़ा राहत भरा रहने वाला है।

ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने करियर-कारोबार और जीवन से जुड़े अहम कार्यों को इसी दौरान करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से मेल-मुलाकात होगी। जिसकी मदद से अटक कार्यों में धीमी गति से ही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में न सिर्फ कार्यक्षेत्र से जुड़ी बल्कि घर-परिवार से संबंधित समस्याएं भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति अथवा किसी जमीन-जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। अचानक से जीवन में तमाम तरह की समस्याएं सामने आने से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि इस दौरान आपके संगी-साथी आपकी ढाल बनेंगे और आपके साथ साए की तरह बने रहेंगे।



मिथुन

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो उम्मीद का दामन बिल्कुल न छोड़ें क्योंकि इस सप्ताह उसमें आ रही बाधाएं स्वतः दूर होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है।

इस दौरान आपके शुभचिंतक आपको नेक सलाह देते हुए नजर आएंगे, जिस पर अमल करके आप अपनी चीजों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी तीर्थ स्थान पर जाने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है। इस पूरे सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक-कार्यों में खूब रहेगा। किसी धार्मिक-आध्यात्मिक व्यक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुक. बले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप आप समझदारी के साथ अपने पैसे का सही जगह निवेश करते हैं तो आपको उससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आएगा।



कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. को किसी भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। रिश्ते-नाते में मिठास बनी रहे और किसी प्रकार की गलतफहमी न पैदा हो इसके लिए स्वजनों के साथ संवाद बनाए रखें।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर-कारोबार के सिलसिले में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसा करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलें। यदि कार्यक्षेत्र पर हालात आपके अनुकूल नहीं हैं तो आप उससे बजाय भागने के उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। भूलकर भी आवेश में आकर नौकरी में बदलाव जैसा फैसला लेने से बचें। सप्ताह के मध्य में घरेलू समस्याओं के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपको आपके विरोधी आप पर हावी होने तथा आपके बनते काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।



सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. को अपनी ऊर्जा, धन और समय का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान कार्य विशेष के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर भी अचानक निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद और नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने कारोबार से जुड़े बड़े फैसले इसी दौरान करने चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप कुछ चीजों को लेकर खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। ऐसे में इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। नौकरीपेशा जातकों इस सप्ताह अपने कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं बेहतर तरीके से पूरे करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा पूर्व में की गई न सिर्फ आपकी मेहनत बेकार जा सकती है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की डांट भी सुनी पड़ सकती है।



कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में मनचाही सफलता और खुशियां मिले तो आपको अपने कार्य और व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना होगा और अपने शुभचिंतकों को नाराज करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपकी किसी बात या व्यवहार से आपके अपने नाराज हो सकते हैं। वाद-विवाद बढ़ने पर वर्षों से बने रिश्ते में दरार आ सकती है। करियर-कारोबार से लेकर घर-परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहे इसके लिए दूसरों से अपेक्षा करने करने की बजाय आपको खुद ही आगे बढ़कर प्रयास करना होगा।

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में कनिष्ठ लोगों के साथ रुखा व्यवहार न करें और अपने वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। यदि आप व्यवसायी हैं तो शार्टकट तरीके से लाभ कमाने से बचें और कागजी काम पूरे करके रखें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन सावधानी के साथ करें।



तुला

तुला राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम और रिश्ते-नाते की दृष्टि से मध्यम फलदायी रहने वाला है।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर-कारोबार से जुड़ा कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह तुला राशि का नौकरीपेशा जातक हो या फिर व्यवसाय से जुड़ा कारोबारी, वह अपना शत प्रतिशत अपने कार्य में देता हुआ नजर आएगा।

खास बात कि उसके प्रयासों को सौभाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और सीनियर आपके कामकाज की खुले मन से प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के अंत तक आपको बड़ा पद अथवा अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी नये कारोबार की शुरुआत करने अथवा किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजी-रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है।



वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभता-सफलता की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। करियर-कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यदि आपके कारोबार में बीते समय से कोई अड़चन आ रही थी इस सप्ताह वह किसी व्यक्ति विशेष की मदद से दूर हो जाएगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आप उसके विस्तार की योजना पर काम करेंगे। आपकी योजना को साकार रूप देने के लिए आपके शुभचिंतक और परिजन पूरी मदद करेंगे। इस संबंध में घर-परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लाभदायी साबित होगी। यह सप्ताह पठन-पाठन एवं शोध से जुड़े कार्यों को करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा।



धनु

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन के नये अवसरों को लेकर आने वाला है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको आलस्य और आशंका को त्याग कर कठिन परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस सप्ताह यदि आप अपने धन, समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आपको आशा से अधिक सफलता और लाभ मिल सकता है। वहीं इसकी अनदेखी करने पर बनते काम बिगड़ जाने से मन में निराशा के भाव जाग सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह खुले हाथ धन खर्च करने से बचना चाहिए अन्यथा सप्ताह के अंत तक उन्हें उधार मांगने की नौबत आ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको कारोबार में लाभ तो होगा लेकिन साथ ही साथ खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है।



मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने करियर-कारोबार में आ रही अड़चनों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र और कारोबार के अलावा निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं भी आपकी बड़ी चिंता का कारण बनेंगी। हालांकि जीवन के कठिन समय में आपके शुभचिंतक एवं परिजन काफी मददगार साबित होंगे और काफी हद तक आप इन समस्याओं का समाधान खोजने में भी कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी भी कार्य को करते समय विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस दौरान स्वजनों के साथ बात-व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आए अन्यथा लंबे समय से बने हुए रिश्तों में दरार आ सकती है। इस सप्ताह खर्च की अधि. कता के चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है।



कुंभ

जीवन में आने वाली छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। करियर और कारोबार की दिशा में किए गये प्रयास सफल होंगे और आपके पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी।

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिर सकता है। सत्तापक्ष से जुड़े लोगों के साथ आपका मेल-मिलाप बढ़ेगा। आपके मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपनी सूझबूझ से अपने विरोधियों पर काबू पाने में कामयाब होंगे। कुंभ राशि के जो जातक तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार करने वालों को बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति से कार्य विशेष के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा।



मीन

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय जहां अनुकूल तो वहीं उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों सप्ताह की शुरुआत में ही निबटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इसी दौरान पूरे मनोयोग से रोजी-रोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से भूमि-भवन से जुड़े विवाद का समाधान निकल सकता है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि उनकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ भी सकती है। ऐसे में अपना काम निकलवाने के लिए लोगों की प्रशंसा करने में जरा भी कंजूसी न करें और सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके घर में कोई धार्मिक अथवा मांग. लिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा-पाठ में बीतेगा।

युद्ध, सत्ता और पत्रकारिता की घटती स्वतंत्रता

ललित गर्ग

10 दिसंबर 2025 तक दुनिया एक भयावह पड़ाव पर पहुँच चुकी थी। पत्रकारों की हत्या का आँकड़ा उस स्तर को छू चुका था, जिसे अब तक केवल चेतावनी के रूप में देखा जाता था। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के अनुसार 2024 में 126 पत्रकार और मीडिया कर्मी मारे गए थे, जो 1992 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद सबसे अधिक था। 2025 में यह संख्या साल खत्म होने से तीन हफ्ते पहले ही बराबर हो गई। इनमें सबसे अधिक कीमत फिलीस्तीनी पत्रकारों ने चुकाई। यह सिर्फ आँकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि उस दुनिया की तस्वीर है जहाँ युद्ध, जलवायु संकट और अनिश्चित राजनीति के बीच सच्चाई तक पहुँचने के रास्ते लगातार संकरे होते जा रहे हैं।

इतिहास गवाह है कि सूचना और स्वतंत्रता का रिश्ता हमेशा गहरा रहा है। अमेरिका के शुरुआती वर्षों से लेकर उन्नीसवीं सदी की यूरोपीय क्रांतियों तक, मुक्त प्रेस को लोकतंत्र की आत्मा माना गया। 1787 में थॉमस जेफरसन ने लिखा था कि अगर उन्हें सरकार के बिना अख़बार या अख़बार के बिना सरकार में से किसी एक को चुनना पड़े, तो वे दूसरे को चुनेंगे। आज, जब हमारे पास मानव इतिहास में किसी भी दौर से ज्यादा मीडिया है, यह कथन और भी प्रासंगिक लगता है। लेकिन विडंबना यह है कि सूचना की भरमार के बावजूद विश्वसनीय जानकारी तक पहुँचना पहले से कठिन हो गया है।

आज सरकारें और तकनीकी कंपनियाँ संदेश पर नियंत्रण पाने की होड़ में हैं और अक्सर सफल भी होती हैं। गाज़ा इसका सबसे कड़ा उदाहरण है, जहाँ अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद फिलीस्तीनी पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन युद्ध को "विशेष सैन्य अभियान" कहकर उसकी रिपोर्टिंग पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये हालात एक पीढ़ी पहले से बिल्कुल अलग हैं। जब सीपीजे ने पहली बार पत्रकारों की मौतों का डेटा जुटाना शुरू किया था, तब शीत युद्ध का



अंत हो रहा था और बर्लिन की दीवार गिर चुकी थी। पूर्व सोवियत ब्लॉक में अंतरराष्ट्रीय मीडिया को अभूतपूर्व स्वतंत्रता मिली थी और वहाँ राजनीतिक बदलावों के साथ-साथ अपेक्षाकृत मुक्त मीडिया का उदय हुआ था।

यह सच है कि उस दौर का मीडिया भी राजनीति और व्यावसायिक प्रभावों से पूरी तरह मुक्त नहीं था, लेकिन एकल पार्टी लाइन की जगह विचारों की बहुलता थी। 1990 का दशक, अपनी तमाम कमियों के बावजूद, प्रेस स्वतंत्रता के लिहाज़ से आज के समय से बेहतर था। इसके बाद 9/11 आया और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ। मीडिया विद्वान और पूर्व विदेशी संवाददाता पीटर ग्रेस्ते ने तर्क दिया है कि आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषाएँ ढीली करके सूचना और विचारों पर नियंत्रण बढ़ाया गया। ग्रेस्ते की यह समझ उनके व्यक्तिगत अनुभव से भी उपजी है। 2013 में मिस्र में उन्हें और उनके सहयोगियों को आतंकवाद के आरोप में हिरासत में लिया गया और ग्रेस्ते ने 400 दिन जेल में बिताए।

उनका अपराध बस इतना था कि उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान मुस्लिम ब्रदरहुड से बात की थी।

सरकारों द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज जो नया है, वह है खुले तौर पर ऐसा करने का गर्व। अमेरिका, जो कभी प्रेस स्वतंत्रता का वैश्विक प्रतीक माना जाता था, अब खुद इस सूची में शामिल दिखता है। पेंटागन तक रिपोर्टों की पहुँच सीमित करने और रिपोर्टिंग पर शर्तें थोपने की नीतियाँ जेफरसन की सोच से बिल्कुल उलट हैं। जेफरसन का यह भी कहना था कि हर व्यक्ति को अख़बार मिलना चाहिए और उसे पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। आज समस्या यही है। मीडिया की संख्या बढ़ी है, लेकिन हर किसी तक उसकी पहुँच नहीं है।

डिजिटल युग में वितरण के साधन समाचार संगठनों के हाथ से निकलकर तकनीकी कंपनियों के पास चले गए हैं। एल्गोरिदम यह तय करते हैं कि हमें क्या दिखेगा और क्या नहीं। गंभीर सवाल

की जगह हल्की-फुल्की सामग्री को प्राथमिकता मिलती है। जहाँ औपचारिक सेंसरशिप नहीं है, वहाँ खबरें ढूँढ़ना मुश्किल और महँगा हो गया है, जबकि सोशल मीडिया मुफ्त और तुरंत उपलब्ध है। दूसरी ओर, सरकारें और आपराधिक तत्व पत्रकारों पर शारीरिक प्रतिबंध लगाते हैं, जिनकी चरम परिणति हत्या तक होती है। शक्तिशाली राजनेता कानूनी कार्रवाइयों या उनकी धमकी से भरोसेमंद मीडिया संस्थानों को चुप कराने की कोशिश करते हैं। पूर्व सोवियत संघ और मध्य पूर्व में युद्धों को कवर कर चुके संवाददाताओं का अनुभव बताता है कि 1990 और 2000 के दशक में सरकारें अक्सर बुरी खबरों को दबाना चाहती थीं, लेकिन आज की तरह सीधे प्रवेश पर रोक कम ही लगाती थीं। गाज़ा और रूस में अंतरराष्ट्रीय पत्रकार उन जगहों तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं जहाँ कहानी घट रही है। वहाँ स्थानीय पत्रकार असाधारण साहस दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है।

इन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद एक सच्चाई साफ है। अगर सरकारें पत्रकारिता को नियंत्रित करने के लिए इतना प्रयास कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि पत्रकारिता की चुनौती देने की शक्ति अब भी बरकरार है। सत्ता जानती है कि स्वतंत्र रिपोर्टिंग उसके कथानक को सवालों के घेरे में ला सकती है। इसलिए वह उसे सीमित करना चाहती है। यह संघर्ष असमान ज़रूर है, लेकिन निर्णायक नहीं। आज जब पत्रकारों की हत्या का आँकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तब यह सिर्फ मीडिया का संकट नहीं, बल्कि लोकतंत्र और समाज का संकट है। क्योंकि जब पत्रकार चुप कराए जाते हैं, तो नागरिकों की आँखें और कान भी बंद कर दिए जाते हैं। सूचना के बिना स्वतंत्र निर्णय संभव नहीं है। इसलिए यह बहस सिर्फ प्रेस की आज़ादी की नहीं, बल्कि उस दुनिया की है जिसमें हम जीना चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ सच तक पहुँचने का अधिकार सुरक्षित हो, या एक ऐसी दुनिया जहाँ सच को नियंत्रित किया जाए। इतिहास बताता है कि पहला रास्ता कठिन ज़रूर है, लेकिन अंततः वही समाजों को आगे बढ़ाता है।



Helpline

पुलिस स्टेशन

बाग-ए-बहू	2459777
बख्शी नगर	2580102
बस स्टैंड	2575151
छहर	2543688
गांधी नगर	2430528
गंग्याल	2482019
नौबाद	2571332
पक्का डांगा	2548610
रेलवे स्टेशन	2472870
सैनिक कॉलोनी	2462212
सतवारी	2430364
चन्नी हिममत	2465164
ट्रांसपोर्ट नगर	2475444
त्रिकुटा नगर	2475133
गांधी नगर	2459660
एसएसपी छहर	2561578
एसपी छहर उत्तर	2547038
एसपी दक्षिण	2433778
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ	
इंडियन एयर लाइन्स	
छहर कार्यालय	2542735
एयर पोर्ट	2430449
जेट एयर वेज	2453999
सिटी ऑफिस	2573399
रेलवे	
रेलवे प्लेटफार्म	131, 132, 2476407
बुकिंग	2470318
आरक्षण	2470315

पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्टेशन

बख्शी नगर	2543557	परेड	2542289
गांधी नगर	2430786	सतवारी कैंट	2452813
कंपनी बाग	2542582	अस्पताल	
नया प्लॉट	2573429	जीएमसी अस्पताल	2584290
पंजतीर्थ	2547537	एस.एम.जी.एस. अस्पताल	2547635
		सी.डी. अस्पताल	2577064
		डेंटल अस्पताल	2544670
		गांधी नगर अस्पताल	2430041
		सरवाल अस्पताल	2579402
		जी.बी. पंत कैंट अस्पताल	2433500
		आयुर्वेदिक कॉलेज	2543661
		सी.आर.पी. अस्पताल	2591105
		आचार्य श्री चंदर	2662536
		मानसिक अस्पताल	2577444
		स्वामी विवेकानंद	2547418
		ब्लड बैंक	2547637
		एम्बुलेंस	2584225, 2575364
		एम्बुलेंस (रेड क्रॉस)	2543739
		नर्सिंग होम	
		मदन अस्पताल	2456727
		मेडिकेयर	2435070
		त्रिवेणी नर्सिंग होम	2452664
		सुविधा नर्सिंग होम	2555965
		अल. फिरोज़ नर्सिंग होम	2545050
		आस्था नर्सिंग होम	2576707
		बी एन चैट्टिबल ट्रस्ट	2505310
		चोपड़ा नर्सिंग होम	2573580
		हरबंस सिंह मेम हॉस्पिटल	2541952
		जीवन ज्योति	2576985
		युद्धवीर नर्सिंग होम	2547821
		मीडियाएड नर्सिंग होम	2466744
		सीता नर्सिंग होम	2435007
		विभूति नर्सिंग होम	2547969
		रामेश्वर नर्सिंग होम	2580601
		बी एन चैट्टिबल	2555631
		महर्षि दयानंद	2545225

दूरसंचार विभाग

डायरेक्टरी पुस्तकालय
फॉल्ट रिपेयर
ट्रंक बुकिंग
बिलिंग शिकायत

जम्मू नगर पालिका

जं. लाइन्स
प्रशासन अधिकारी
स्वास्थ्य अधिकारी

डाक सेवाएँ

मुख्य डाकघर छहर
गाँधी नगर

अग्निशमन सेवाएँ

नियंत्रण कक्ष
छहर
गाँधी नगर
नहर
गंग्याल

रखोई गैस डीलर

चिनाब गैस
गुलमीर गैस
जैकफेड
एचपी गैस
शिवांगी गैस
तवी गैस

पावर हाउस

गाँधी नगर
नहर रोड
जानीपुर
नाजक नगर

सीबीके ने पशुधन धोखाधड़ी मामले में आरोप पत्र दाखिल किया

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : कश्मीर क्राइम ब्रांच (सीबीके) ने आज पशुधन धोखाधड़ी के एक उच्च मूल्य मामले में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें एक पशु व्यापारी को कथित तौर पर सरकारी कल्याण योजना का झूठा हवाला देकर लाखों रुपये का चूना लगाया गया था।

यहां जारी एक बयान के अनुसार, रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 17/2023 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीनगर की अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें। आरोपी की पहचान मुनीर अहमद कटारिया, पुत्र नूरुद्दीन कटारिया, निवासी उरी सलामाबाद, जो वर्तमान में बारामूला जिले के शुत्रलू रोहामा में रह रहा है, के रूप में हुई है।

है।

सीबीके ने बताया कि मामला पशुधन की बिक्री के संबंध में धोखाधड़ी और बड़ी रकम के गबन की लिखित शिकायत से शुरू हुआ।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे सरकारी अनुसूचित जनजाति कोटा योजना के तहत भुगतान का आश्वासन देकर गाय और भेड़ की आपूर्ति करने के लिए प्रेरित किया गया था।

जांच के दौरान, सीबीके ने पाया कि शिकायतकर्ता, जो मवेशी और भेड़ की खरीद-बिक्री का व्यवसाय करता है, ने कई लाख रुपये मूल्य के गाय और भेड़ सहित पशुधन की आपूर्ति की थी। सीबीके ने कहा,

“पशुधन में उसका विश्वास जीतने के लिए आंशिक भुगतान किया गया था। बाद में, आरोपी ने 30 लाख रुपये के कई चेक जारी किए, जो अपर्याप्त राशि के कारण सभी अस्वीकृत हो गए।”

एजेंसी ने आगे कहा कि बार-बार आश्वासन देने के बावजूद, शेष भुगतान कभी नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

जांच में आगे पता चला कि आरोपी ने सरकारी कल्याणकारी योजना के तहत खरीद के झूठे बहाने से भुमराह करने वाले समझौते करके और धमकाने और फर्जी चेक जारी करके सुनियोजित तरीके से काम किया, जिससे शिकायतकर्ता को अनुचित नुकसान हुआ और उसने खुद को अनुचित लाभ पहुंचाया।

जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर, सीबीके ने कहा कि आरपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध पूरी तरह से साबित हो गए हैं, और न्यायिक निर्णय के लिए सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर में सेना ने शीतकालीन अभियान तेज कर दिए हैं



सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : सूत्रों ने शनिवार को बताया कि भीषण ठंड और दुर्गम इलाकों के बीच, भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के किश्तवार और डोडा जिलों में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं ताकि भीषण सर्दी का फायदा उठाकर छिपने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी आतंकवादियों का पीछा किया जा सके और उन्हें निष्क्रिय किया जा सके।

परंपरागत रूप से, कश्मीर घाटी में 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलने वाले 40 दिवसीय शिबिर कलांश (सर्दियों का सबसे कठोर चरण) के प्रारंभ के साथ ही आतंकवादी गतिविधियों में अस्थायी ठहराव आ जाता है, क्योंकि संचार मार्ग बंद हो जाते हैं और भारी बर्फबारी से पहाड़ी क्षेत्र अलग-थलग पड़ जाते हैं। हालांकि, रक्षा प्रतिष्ठान के एक सूत्र ने बताया कि इस सर्दी में सेना और अन्य सुरक्षा बलों के परिचालन दृष्टिकोण में एक निर्णायक बदलाव आया है। सूत्रों के अनुसार

, सेना ने गतिविधियों को कम करने के बजाय एक सक्रिय शीतकालीन रणनीति अपनाई है और संभावित आतंकवादी ठिकानों पर दबाव बनाए रखने के लिए बर्फ से ढके इलाकों में अस्थायी अड्डे और निगरानी चौकियां स्थापित की हैं। शून्य से नीचे के तापमान और सीमित दृश्यता में परिचालन करते हुए, सेना के गश्त दल नियमित रूप से उच्च ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाओं, घाटियों और वन क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं ताकि आतंकवादियों को कोई पनाह न

मिल सके। विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव आतंकवाद विरोधी रणनीति में एक विकास का संकेत है, जो मौसम या भूभाग की परवाह किए बिना, सेना की अनुकूलन क्षमता और परिचालन गति बनाए रखने के उसके संकल्प को रेखांकित करता है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि विभिन्न खुफिया एजेंसियों के आकलन के अनुसार, वर्तमान में जम्मू क्षेत्र में लगभग 30-35 पाकिस्तानी आतंकवादी मौजूद हैं।

पिछले कुछ महीनों में जुटाई गई जानकारीयों से पता चलता है कि सफल आतंकवाद-विरोधी अभियानों के चलते घिरे हुए ये पाकिस्तानी आतंकवादी समूह क्षेत्र के ऊंचे और मध्य पर्वतीय इलाकों में और भी गहराई में चले गए हैं, जो अब आबादी रहित हैं। सूत्रों का कहना है कि ये आतंकवादी सुरक्षा बलों से सीधे टकराव से बचने और पकड़े जाने से बचने के लिए अस्थायी शीतकालीन ठिकाने तलाश रहे हैं। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इन आतंकवादी समूहों के बचे हुए सदस्य स्थानीय ग्रामीणों को आश्रय और भोजन आपूर्ति के लिए धमकाने या डराने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि स्थानीय लोगों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच उनका समर्थन काफी कम हो गया है।

सूत्रों के अनुसार, निचले इलाकों में स्थानीय समर्थन के कम होने और लगातार सुरक्षा निगरानी ने उन्हें अलग-थलग कर दिया है, जिससे उनके फिर से संगठित होने या समन्वित हमलों की योजना बनाने की क्षमता और भी सीमित हो गई है। सूत्रों

के मुताबिक, सेना ने किश्तवार और डोडा

जिलों में अपने आतंकवाद-विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, जमा देने वाली ठंड, दुर्गम भूभाग और भारी हिमपात की परवाह किए बिना, सेना की टुकड़ियों ने ऊंचे और बर्फ से ढके इलाकों में अपनी परिचालन क्षमता का विस्तार किया है ताकि उन पाकिस्तानी आतंकवादियों का पीछा किया जा सके और उन्हें निष्क्रिय किया जा सके जो इस कठोर मौसम का फायदा उठाकर छिपने की कोशिश कर रहे हैं। इस वर्ष की आतंकवाद विरोधी रणनीति की एक प्रमुख विशेषता अभियानों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण रहा है।

एक अन्य सूत्र ने बताया कि सेना नागरिक प्रशासन, जम्मू-कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), विशेष अभियान समूह (एसओजी), वन रक्षकों और ग्राम रक्षा रक्षकों (वीडीजी) सहित कई सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वित प्रयास का नेतृत्व कर रही है। सूत्र ने

आगे बताया कि यह अंतर-एजेंसी सहयोग खुफिया जानकारी के निर्बाध आदान-प्रदान, संसाधनों के अधिकतम उपयोग और बेहतर परिचालन निष्पादन को सुनिश्चित करता है।

आतंकवादियों की गतिविधियों और छिपने के तरीकों की सटीक स्थितिगत तस्वीर तैयार करने के लिए कई एजेंसियों से प्राप्त खुफिया जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। रक्षा सूत्रों के अनुसार, खुफिया जानकारी की पुष्टि हो जाने के बाद, समन्वित संयुक्त अभियान की योजना बनाई जाती है और उसे शुरू किया जाता है, जिससे कार्यों में दोहराव कम से कम हो और सामरिक सटीकता के साथ अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित हो सके। उन्होंने आगे कहा कि जमीनी इकाइयों और खुफिया तंत्रों के बीच तालमेल ने प्रतिक्रिया समय को बढ़ाया है, जिससे सुरक्षा बलों को कार्यवाही योग्य सूचना मिलते ही तुरंत कार्यवाही करने में मदद मिली है। एक सूत्र ने बताया कि इस सर्दी में सेना और अन्य बलों का मुख्य ध्यान दो बातों पर है—ज्ञात क्षेत्रों के भीतर बचे हुए आतंकवादी ठिकानों को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना कि आतंकवादी दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक ही सीमित रहें।

समाज सेवक सतपाल वर्मा ने वृद्ध आश्रम कठुआ में बुजुर्गों को बांटे कंबल, माता-पिता की सेवा का दिया संदेश



सबका जम्मू कश्मीर

मढ़ीन/कठुआ। तहसील मढ़ीन के साथ लगते कोर्टपुन के रहने वाले समाज सेवक सतपाल वर्मा ने बुधवार को वृद्ध आश्रम कठुआ में बुजुर्गों को कंबल वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल सेवा करना नहीं, बल्कि समाज को यह संदेश देना है कि लोग अपने माता-पिता की सेवा स्वयं करें।

सतपाल वर्मा ने कहा कि बुजुर्गों को इस उम्र में बच्चों के साथ और घर के सहारे की जरूरत होती है,

न कि वृद्ध आश्रम की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने माता-पिता को घर पर रखें और उनकी देखभाल करें।

उन्होंने कहा कि जिस तरह माता-पिता अपने बच्चों के बचपन में उनकी हर जरूरत पूरी करते हैं, उसी तरह यह समय बच्चों का कर्तव्य होता है कि वे अपने माता-पिता को सम्मान, स्नेह और हर सुख दें। सतपाल वर्मा ने अंत में समाज से आग्रह किया कि माता-पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ने के बजाय उन्हें अपने घर में रखकर उनकी सेवा करें, यही सच्ची मानव सेवा है।

माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की सभी 50 सीटें हिंदुओं के लिए आरक्षित की जाएं : तोगड़िया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद (एएचपी) के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने आज मांग की कि जम्मू और कश्मीर के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सभी 50 सीटें हिंदुओं के लिए आरक्षित की जाएं और ऐसा न किए जाने पर आंदोलन को और तीव्र करने की चेतावनी दी।

तोगड़िया ने कहा कि भारत फुलिम डॉक्टरों की शिक्षा के लिए हिंदुओं द्वारा दिए गए दान के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगा। शक्ति नगर में राष्ट्रीय बजरंग दल के एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, “मैं उपराज्यपाल से इस मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूँ, अन्यथा मैं स्वयं कोई रास्ता निकालूंगा।”

दक्षिणपंथी हिंदू नेता ने कहा कि वे जम्मू क्षेत्र के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तोगड़िया ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इस अन्याय से अनभिज्ञ हैं। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता तोगड़िया फिलहाल जम्मू क्षेत्र के छह दिवसीय दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत बुधवार को कठुआ से हुई। तोगड़िया ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से श्री माता वैष्णो देवी सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने का आग्रह किया।

“उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो मेरे बड़े भाई के समान हैं, उन्हें प्रवेश सूची तुरंत रद्द कर देनी चाहिए। अन्यथा, मैं हर गाँव में जाकर श्रद्धालुओं से आग्रह करूंगा कि वे वैष्णो देवी मंदिर में दान न करें और इसके बजाय चावल चढ़ाएँ।” हम अपनी कमाई से दान करेंगे, लेकिन कश्मीर से मुस्लिम डॉक्टर आएंगे इस देश के हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे,” तोगड़िया ने कहा।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह अन्याय नहीं रोका गया, तो पूरा देश जम्मू के लोगों के साथ है। “हमने 2008 के अमरनाथ जी भूमि विवाद आंदोलन के दौरान यह दिखाया था और जरूरत पड़ने पर हम इसे फिर से कर सकते हैं,” उन्होंने आगे कहा।

उन्होंने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हिंदुओं के पैसे का इस्तेमाल दूसरे समुदाय के डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए किया जाए। जब छठनसे पूछा गया कि राज्य में उपराज्यपाल का शासन होने के बावजूद ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल को इस मुद्दे की जानकारी न हो और मुझे उम्मीद है कि वे निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे और जम्मू को न्याय मिलेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कथित अत्याचारों के बारे में पूछे जाने पर, तोगड़िया ने केंद्र सरकार को पड़ोसी देश को नमक, चावल और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की आपूर्ति रोकने का सुझाव दिया।

आपदा प्रभावित परियोजनाओं के पुनर्निर्माण व अमृत कार्यों की डीसी कठुआ ने की समीक्षा



सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : उपायुक्त कठुआ राजेश शर्मा ने हालिया बाढ़ व भारी बारिश से क्षतिग्रस्त विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण कर उनके पुनर्निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को एसडीआरएफ मानकों के तहत समयबद्ध और टिकाऊ पुनर्निर्माण सुनिश्चित

करने के निर्देश दिए।

लखनपुर में उपायुक्त ने पशुपालन निदेशक जम्मू डॉ. संजय गुप्ता और सीएचओ डॉ. जुगल किशोर गुप्ता के साथ रवि नदी के किनारे स्थित रिंडरपेस्ट चेकपोस्ट भवन का निरीक्षण किया, जो बाढ़ से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। उपायुक्त ने क्षति का जायजा लेते हुए विभाग को शीघ्र व्यापक पुनर्निर्माण प्रस्ताव तैयार करने और

मजबूत व टिकाऊ निर्माण पद्धतियां अपनाने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया, जहां स्थायी पुनर्निर्माण योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उन्होंने क्षति आकलन और डीपीआर की प्रगति की समीक्षा करते हुए एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने और आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की बहाली को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

बाद में उपायुक्त ने मुख्य योजना अधिकारी रंजीत ठाकुर और एक्सईएन पीएचई के साथ परोल नगर पालिका क्षेत्रों का दौरा कर डल्ट्ज 2.0 के तहत चल रहे जलापूर्ति व सीवरेज कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता और गति पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्यदायी एजेंसियों को तय समय-सीमा और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि पुनर्निर्माण कार्यों और डल्ट्ज परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है, ताकि टिकाऊ विकास और जन-सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

नया साल

कंधे पर गैती उठाए
एक नन्हा मजदूर
नंगे पांव, अर्द्ध वस्त्र
कड़कड़ाती सर्दी
सड़क के किनारे
अपनी मजदूर मां के पीछे पीछे
चल रहा है
भविष्य से बेखबर
सूर्य ढलने की ओर
खूब सजे हैं बाजार
मिठाईयों की सुरभि
ललचाती यहिबा
कुछ माटी के दीपक
रंग बिरंगी मोमबतियां
क्या मालूम?
किस घर में दंगी रौशनी
मजदूर मां ने रोज की तरह
गुले सड़े फल लिए
कुछ आटा, कुछ दाल
मछलियों के फेंके
हुए सिर उठाए
थकान की टूटन लिए
चल पड़ी झोंपड़ी की ओर
ईंटों के चूल्हे पर
रोटियां छेंकीं
थका मांदा शरीर लिए



लेट गई ज़मीन की चारपाई पर
लपक के सो गए बच्चे उस के
साथ
ऊँचे महलों में पटाखे चले
रात के बारह बजे
रौशनियों से भरा आसमान
नन्हें मजदूर ने उठ कर पूछा,
मां, यह क्या हो रहा है?
मां ने कहा, चुप, सो जा
सुबह तड़के जाना (जाना) हैं
मजदूरी के लिए,
कुछ नहीं है,
कमबख्त, नया साल है।

बलविन्दर बालम
ओंकार नगर,
गुरदासपुर (पंजाब) 9815625409

नववर्ष के उपलक्ष पर निरंकारी सतगुरु का खुशियों और आशीष भरा पावन संदेश

सबका जम्मू कश्मीर

नौशहरा : 'निरंकार की रजा में जीवन जीना ही सच्ची साधना है।' यह प्रेरणादायक प्रवचन निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा नववर्ष के शुभ अवसर पर दिल्ली स्थित ग्राउंड नम्बर 8, निरंकारी चौक, बुराड़ी रोड में आयोजित विशेष सत्संग समारोह में व्यक्त किए गये। इस सत्संग में दिल्ली, एन.सी.आर. सहित विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालुगण सम्मिलित हुए। सभी भक्तों ने नव वर्ष के प्रथम दिन सतगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन सान्निध्य में उनके दिव्य दर्शन और प्रेरणादायक प्रवचनों से आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का सुखद आनंद प्राप्त किया।

सतगुरु माता जी ने अपने उद्बोधन में फरमाया कि नववर्ष का प्रथम दिवस हमें संता. के वचनों को सुनने और उन्हें जीवन में अपनाने का अनमोल अवसर देता है। जहाँ संसार वर्ष की शुरुआत मौज-मस्ती से करता है, वहीं संत सत्य और सत्संग का मार्ग चुनते हैं। सत्संग से आरंभ हुआ जीवन हर पल निरंकार के एहसास को और अधिक दृढ़ करता चला जाता है।

तार्किक रूप से नववर्ष केवल धरती का सूर्य



के चारों ओर एक चक्कर और ऋतुओं का परिवर्तन है। हम शुभकामनाएँ देते हैं और नए संकल्प लेते हैं, पर वास्तविक परिवर्तन तभी सार्थक होता है जब वह भीतर से आए। संत आत्ममंथन द्वारा सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं और निरंकार को सर्वोपरि मानते हुए सेवा, सुमि. रन और सत्संग को जीवन की प्राथमिकता बनाते हैं।

सतगुरु माता जी ने कहा कि एक भक्त की

यही कामना होती है कि हर नया वर्ष उसे पहले से अधिक सेवा, सुमिरन और सत्संग से जोड़े, साथ ही वह अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को भी पूरी निष्ठा से निभाए। जब जीवन स्वयं संद. 'श बन जाए और कर्म शब्दों से अधिक बोलें, तभी सच्ची साधना का स्वरूप प्रकट होता है। इसी क्षण में, पूरी चेतन अवस्था के साथ, निरंकार के एहसास में जीना ही वास्तविक जीवन है, क्योंकि भूत और भविष्य माया का रूप हैं। जब मन में यह विश्वास दृढ़ हो जाए कि कल भी दातार की रजा थी और आज भी उसकी कृपा है, तो चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है और जीवन सहज और संतुलित बन जाता है। नववर्ष केवल तारीख का परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रेम, मिठास, सौम्यता और समझ को अपनाने का अवसर है। मनमुटाव और द्वेष से दूर रहकर, दूसरों के भावों को समझते हुए, दोषों पर पर्दा डालकर गुणों को अपनाना ही सच्ची भक्ति है।

हर श्वास में सुमिरन हो, हर क्षण में निरंकार का वास हो, यही नववर्ष का सच्चा अर्थ और संदेश है। नव वर्ष के अवसर पर सतगुरु माता जी ने अंत में सभी श्रद्धालुओं के लिए सुख, समृद्धि और आनंदमय जीवन की शुभकामनाएं प्रदान की।

मेजर जनरल अनुपिंदर बेवली का एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी दौरा



सबका जम्मू कश्मीर

नग्रोता : जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) मेजर जनरल अनुपिंदर बेवली, वीएसएम ने 22 दिसंबर 2025 को एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी (एनटीए), नग्रोता का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस शिविर 2026 के लिए तैयार किए जा रहे एनसीसी दल के प्रशिक्षण, अनुशासन और समग्र तैयारियों की समीक्षा की। यह दौरा आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रम के मद्देनजर कैडेटों के मनोबल और तैयारी को परखने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के बालक एवं बालिका कैडेटों से मिलकर बना यह दल पिछले सात सप्ताह से एनटीए नग्रोता में गहन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। यह दल नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस शिविर में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख एनसीसी निदेशालय का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों ने परेड, ड्रिल, शारीरिक दक्षता, सांस्कृतिक गतिविधियों और नेतृत्व कौशल में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है।

दौरे के दौरान मेजर जनरल बेवली ने श्रेष्ठ कैडेटों और युथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए चयनित होने की आकांक्षा रखने वाले कैडेटों से संवाद किया। उन्होंने कर्तव्य पथ पर परेड, गार्ड ऑफ ऑनर और प्रधानमंत्री रैली के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल कैडेटों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की। इसके अलावा फ्लैग एरिया परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया, जहां कैडेटों द्वारा तैयार किए गए मॉडल और विषयगत प्रदर्शनों में रचनात्मकता और तकनीकी दक्षता देखने को मिली, जिसकी एडीजी ने सराहना की। कार्यक्रम के दौरान कैडेटों ने समूह गीत, समूह नृत्य और बैले के माध्यम से देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द के संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने न केवल कैडेटों की कला प्रतिभा को उजागर किया, बल्कि उनकी भावनात्मक और वैचारिक परिपक्वता को भी दर्शाया।

कैडेटों को संबोधित करते हुए मेजर जनरल बेवली ने युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने में एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद गुणवत्ता बढ़ाने हेतु अग्रबतियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का नया मानक जारी किया

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का भारतीय मानक आईएस 19412:2025 दृ अग्रबत्ती दृ विनिर्देशन जारी किया। यह मानक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडप में जारी किया गया।

नए अधिसूचित मानक में अग्रबतियों में कुछ कीटनाशक रसायनों और कृत्रिम सुगंधित पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो मानव स्वास्थ्य, घर के अंदर की वायु गुणवत्ता

और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए, आईएस 19412:2025 में अग्रबतियों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित पदार्थों की सूची दी गई है। इसमें एलेथिन, परमेथिन, साइपरमेथिन, डेल्टामेथिन और फिप्रोनिन जैसे कुछ कीटनाशक रसायन, साथ ही बेंजाइल साइनाइड, एथिल एक्रिलेट और डाइफेनिलामाइन जैसे कृत्रिम सुगंधित पदार्थ शामिल हैं। इनमें संस्थान (सीईसी आरआई), कराईकुडी, सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई), हैदराबाद; सीएसआईआर-केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई), चेन्नई; सीएसआईआर-

संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र (एसआईआरसी), चेन्नई; सीएसआईआर-कोशिकीय और आणविक जीवविज्ञान केंद्र (सीसीएमबी)। हैदराबाद और सीएसआईआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद ने बैठक में भाग लिया और अपनी प्रमुख उपलब्धियों तथा भविष्य की योजनाओं को प्रस्तुत किया। डॉ. सिंह को सामूहिक रूप से जानकारी देते हुए, सीएसआईआर- सीईसीआरआई के निदेशक डॉ. के. रामेशा ने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा भंडारण और स्वच्छ ऊर्जा में सीएसआईआर-सीईसीआरआई के कार्यों को रेखांकित किया।

नव वर्ष पर अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे रठुआ गांव में भजन-कीर्तन, शांति और सुख-समृद्धि की कामना



सबका जम्मू कश्मीर

रठुआ/मढ़ीन/हीरानगर : 31 दिसंबर को जहां लोग नव वर्ष का स्वागत अलग-अलग तरीकों से करते हैं, वहीं जिला कठुआ की तहसीररठुआ

हीरानगर से सटे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव रठुआ में नव वर्ष के अवसर पर भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। जीरो लाइन के पास बसे इस गांव में स्थानीय लोग ने भगवान का सिमरन कर नए साल का

स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने परिवार के साथ सुख-शांति से जीवन बिताने की कामना की। भजन-कीर्तन के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि आने वाला नव वर्ष उनके और उनके परिवारों के लिए मंगलमय हो तथा सीमा क्षेत्र में रहने के कारण किसी भी तरह की परेशानी या विस्थापन की स्थिति न बने।

कार्यक्रम में मौजूद पूर्व कप्तान सोमराज ने कहा कि वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अंत. रराष्ट्रीय सीमा पर हमेशा शांति बनी रहे। उन्होंने कहा कि बिना कारण गोलीबारी होने से दोनों देशों की सेनाओं को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है, जिससे सीमा पर रहने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आशा जताई कि ईश्वर इन समस्याओं का समाधान करेंगे और सीमा क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होगी। अंत में उन्होंने पूरे देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं और बेहतर भविष्य की कामना की।

एलजी सिन्हा : सिख गुरुओं के सर्वोच्च बलिदान
एकता और अखंडता को कायम रखते हैं



सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : वीर बाल दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साहिबजादों, माता गुजरी जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल ने कहा, "हम साहिबजादों की अद्वितीय वीरता, बलिदान और साहस, माता गुजरी जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की प्रतिबद्धता को याद करते हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।" वे गुरुद्वारा दिगियाना आश्रम में अखिल जम्मू कश्मीर सिख समन्वय समिति द्वारा आयोजित विशेष शहीदी समागम रसफर-ए-शहादत में बोल रहे थे। उन्होंने आगे कहा, "हमारे सिख गुरुओं का सर्वोच्च बलिदान हम सभी को राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है।" लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, "हमारा यह दृढ़ प्रयास होना चाहिए कि हम एक समृद्ध देश का निर्माण करें जो एकजुट हो और अपनी विविधता में मजबूत हो।" लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आगे कहा कि भक्ति, वीरता और गौरव से ओतप्रोत सिख परंपरा, "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की अमूल्य भावना का सही मायने में प्रतीक है।

इंस्पेक्टर अंकुश ज्योति को उत्कृष्ट सेवा के लिए
क्ल-ट कमेंडेशन मेडल से सम्मान

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ/जम्मू। साल 2025 के दौरान बेहतरीन और सराहनीय सेवा देने पर इंस्पेक्टर अंकुश ज्योति को क्ल-ट कमेंडेशन मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उनकी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

इंस्पेक्टर अंकुश ज्योति ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रोफेशनलिज्म और निष्ठा के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनकी निस्वार्थ सेवा ने न केवल फोर्स का गौरव



बढ़ाया, बल्कि समाज में भी सुरक्षा और भरोसे की भावना को मजबूत किया है।

उनकी इस उपलब्धि पर विभाग के अधिकारियों और सहयोगियों ने उन्हें हार्दिक बधाई दी और इसे अन्य कर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत।

पुंछ में कुख्यात ड्रग तस्कर की 60 लाख की संपत्ति जब्त, सेफेमा के तहत कार्रवाई की पुष्टि



राजेश कुमार

पुंछ : नशीली दवाओं की तस्करी और नार्को-आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस पुंछ को अहम सफलता मिली है। थुड। कानून के तहत एक कुख्यात ड्रग तस्कर की आवासीय संपत्ति को जब्त करने की पुष्टि कर दी गई है।

यह संपत्ति सज्जाद हुसैन शाह पुत्र सरफराज हुसैन शाह, निवासी पोठा, तहसील सुरनकोट की

है, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामला में शामिल रहा है। करीब 60 लाख रुपये की कीमत वाला यह मकान पहले ही पुलिस थाना सुरनकोट द्वारा सीज किया जा चुका था, जिसे अब कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद थुड। के तहत अंतिम रूप से जब्त कर लिया गया है।

आरोपी इस समय पिट एनडीपीएस के तहत जिला जेल उधमपुर में बंद है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से नशा तस्करी और नार्को-टेरर नेटवर्क को आर्थिक रूप से कमजा

र करने में मदद मिलेगी।

जिला पुलिस पुंछ ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ खुफिया जानकारी के आधार पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। हाल के महीनों में कई करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं और संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज किया गया है।

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नशा तस्करी से जुड़ी किसी भी जानकारी को साझा कर इस अभियान में सहयोग करें।

प्रधानमंत्री 27 और 28 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 और 28 दिसंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह सम्मेलन राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर आधारित और सतत संवाद के माध्यम से केंद्र-राज्य साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद

के दृष्टिकोण पर आधारित यह सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है जहां केंद्र और राज्य भारत की मानव पूंजी क्षमता को अधिकतम करने तथा समावेशी भविष्य के लिए तैयार विकास को गति देने के लिए एक एकीकृत प्रारूप तैयार करने के लिए सहयोग करते हैं।

26 से 28 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन में एक साझा विकास एजेंडा को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से गहन

विचार-विमर्श किया जाएगा। यह सम्मेलन भारत की जनसंख्या को केवल जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में देखने के बजाय नागरिकों को मानव पूंजी के रूप में स्थापित करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई का आधार तैयार करेगा।

इसके लिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत करने, कौशल विकास पहलों को आगे बढ़ाने और देश भर में भविष्य के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन

करने के लिए ठोस रणनीतियां विकसित की जाएंगी।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर, पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय विकसित भारत के लिए मानव पूंजी होगी, जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां और रणनीतियों को शामिल किया जाएगा।

सबका जम्मू कश्मीर

“पत्रकारों की आवश्यकता”

‘सबका जम्मू कश्मीर’ हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र

के लिए जम्मू कश्मीर के सभी जिला के लिए पत्रकारों की आवश्यकता है इच्छुक पत्रकार संपर्क करें

योग्यता:

- पत्रकारिता में अनुभव
- उत्कृष्ट लेखन और संपादन कौशल
- सोशल मीडिया घरेलू में काम करने का अनुभव

अपना बायोडाटा ई.मेल करें
sabbajammukashmir@gmail.com

संपर्क नंबर :
6005134383

सबका जम्मू कश्मीर

नाम परिवर्तन, तहसीलदार नोटिस, शोक सदेश, गुमशुदा सूचना, बेदखली, हुडा नोटिस, वैवाहिक, सार्वजनिक सूचना इत्यादि विज्ञापन

MOB:- +91 60051-34383, +91 87170 07205

डीसी कठुआ ने 'कैच द रेन' कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ, 02 जनवरी: उपायुक्त कठुआ राजेश शर्मा ने आज जिले में जल शक्ति अभियान के तहत चल रहे 'कैच द रेन' कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की।

बैठक में वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों के संरक्षण और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की स्थिति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जिले के सभी जल स्रोतों और बनाए गए जल संरक्षण कार्यों की सही मैपिंग की जाए, ताकि भविष्य की योजना बेहतर तरीके से बनाई जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित विभाग पोर्टल पर समय-समय पर कार्यों की जानकारी अपडेट करें और पारदर्शिता के लिए जियो-टैग्ड फोटो अपलोड करना सुनिश्चित करें। डीसी ने जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को विभागों की जिम्मेदारी के अनुसार करने और भौतिक व वित्तीय प्रगति की समय पर रिपोर्ट देने पर जोर दिया।

उपायुक्त ने आम लोगों की भागीदारी को



जरूरी बताते हुए जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पानी का सही उपयोग और स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन मजबूत करना समय की जरूरत

है।

बैठक में अपर उपायुक्त कठुआ सुरेंद्र मोहन शर्मा, मुख्य योजना अधिकारी रंजीत ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर

छोटा विज्ञापन बड़ा फायदा क्लासीफाईड

आवश्यकता प्रॉपर्टी लोन व्यापार ज्योतिष

बुकिंग के लिए संपर्क करें

MOB:- +91 60051-34383, +91 87170 07205

K2 LADIES GYM & K2 LIBRARY

GET IN SHAPE START TODAY

Workout join our gym

CONTACT NO.9541518471

AIRWAN ROAD NAGRI PAROLE KATHUA

JMB UPVC & ALUMINIUM INDUSTRY

AUTHORISED BY PROMINANCE UPVC WINDOW SYTSEM

A WORK OF ART

A FEAT OF ENGINEERING

PROFILE 20 YEARS WARRANTY

ACCESSORIES 10 YEARS WARRANTY

JMB UPVC & ALUMINIUM INDUSTRY

AUTHORISED BY PROMINANCE UPVC WINDOW SYTSEM

Address: Sherpur, Kathua (J&K) | M.: 9086038088, 9419162407

Email: jmbupvc@gmail.com